



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2011/फाल्गुन 9, 1932

No. 101]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2011/PHALGUNA 9, 1932

विदेश मंत्रालय

(सीपीवी प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 115(अ).—जबकि, स्वापक दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध अनुच्छेद 29 (1) के अनुसार 1988 संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (जिसे इसमें इसके बाद अभिसमय कहा गया है) जो 1 नवम्बर, 1990 को प्रभावी हुआ, में भारत सरकार और कोशिया सरकार पक्षकार है।

जबकि इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सृजित अपराधों को निर्दिष्ट किया गया है ;

जबकि इस अभिसमय का अनुच्छेद 6 उन अपराधों को प्रत्यर्पणीय बनता है ;

जबकि इस द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि न होने की स्थिति में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सृजित अपराधों के लिए अभिसमय प्रत्यर्पण के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है ;

जबकि वर्तमान में भारत सरकार और कोशिया सरकार के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि कार्यरत नहीं है ;

जबकि भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 3 की उपधारा (4) केन्द्रीय सरकार को किसी अभिसमय, जिसमें भारत और विदेशी राज्य पक्ष हो, उस अभिसमय में बताए गए अपराधों के लिए प्रत्यर्पण के लिए भारत और उस विदेशी राज्य के साथ संपन्न हो को, अधिसूचित आदेश द्वारा प्रत्यर्पण संधि के रूप में मानने की शक्ति प्रदान करता है ; और

जबकि स्वापक दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध 1988 संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पाठ में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :-

स्वापक दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

19 दिसम्बर, 1988 को सम्मेलन की 6ठी पूर्ण बैठक में पारित

इस अभिसमय के पक्षकार

दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों, जो मानव जाति के स्वास्थ्य और कल्याण पर एक गहरा खतरा और समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आधार को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, के विस्तार और अवैध उत्पादन के बढ़ते चलन से गंभीर रूप से चिंतित हैं;

स्वापक दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों का समाज के विभिन्न संगठनों के लगातार बढ़ते संबंधों और विशेष रूप से इस बात से कि दवाओं के अवैध व्यापार के लिए विश्व के अनेक भागों में बच्चों का उपयोग किया जाता है, से भी अत्यधिक चिंतित हैं ;

अवैध व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए आपराधिक मामलों में प्रभावी कानूनी उपायों को सुदृढ़ करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी स्वीकार करते हुए ;

एक व्यापक प्रभावी और कारगर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तैयार करने, जो विशेषरूप से अवैध व्यापार के विरुद्ध हो और जिसमें कुल मिलाकर समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार हो, विशेषकर उन पहलुओं जिनकी स्वापक दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के क्षेत्र में वर्तमान संघियों में कल्पना न की गई हो, की इच्छा से ;

निम्नलिखितानुसार सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद एक परिभाषाएं

संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होने तक अथवा स्पष्टरूप से अन्यथा इंगित किए जाने की स्थिति को छोड़कर पूरे अभिसमय के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

(क) ' बोर्ड ' का अर्थ स्वापक दवाओं पर एकल अभिसमय, 1961 द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड और प्रोटोकोल 1972 द्वारा यथा संशोधित वह स्वापक दवाओं पर एकल अभिसमय, 1961;

(ख) ' भांग का पौधा ' का अर्थ, भांग के किस्म का कोई पौधा ;

(ग) ' कोका बुश ' का अर्थ, एरिथ्रोक्सीलोन प्रकार की जाति का कोई पौधा ;

(घ) ' कर्मिशियल कैरियर ' का अर्थ पारिश्रमिक किराए अथवा अन्य लाभ के लिए व्यक्तियों, माल अथवा डाक में लगा कोई व्यक्ति, अथवा जनता, निजी अथवा अन्य निकाय

(ङ) ' कमीशन ' का अर्थ संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का नशीली दवाओं का आयोग

(च) ' समापहरण ' में जहां लागू हो जब्ती शामिल है अर्थात् किसी न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश से संपत्ति का स्थायी वंचन ;

(छ) इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैरा I के अनुसार स्थापित अपराध करने में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से इस अभिसमय में संलग्न तालिका I और II में दी गई गैर कानूनी स्वापकों, मनः प्रभावी पदार्थों, पदार्थों अथवा उसके प्रतिस्थापित पदार्थों का

उनके सक्षम अधिकारियों की जानकारी और उनकी देख-रेख में एक या एक से अधिक देशों के क्षेत्रों से निकालने अथवा में ले जाने की संदिग्ध खेप की अनुमति देने की तकनीक का अर्थ “नियंत्रित डिलीवरी” है ;

(ज) अभिसमय 1961 का अर्थ स्वापकों पर एकल अभिसमय, 1961 ;

स्वापकों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध उत्पादन, वितरण और व्यापार के उद्देश्य के लिए उपभोक्ता बाजार , जो अनिश्चित गंभीर खतरा बना हुआ है ।

अवैध व्यापार और अन्य आपराधिक गतिविधि संबंधित संगठन, जो अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाते हैं और राज्य के स्थायित्व, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा हैं, के बीच संपर्कों को स्वीकार करते हुए;

यह भी स्वीकार करते हुए कि अवैध व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि है जिसको रोकने के लिए तत्काल ध्यान और उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ।

इस बात से अवगत होते हुए कि अवैध व्यापार से भारी वित्तीय लाभ और संपदा पैदा होती है जिसकी सहायता से परराष्ट्रीय आपराधिक संगठन सरकार में वैध वाणिज्यिक एवं वित्तीय व्यापार में और समाज में सभी स्तरों पर घुसपैठ बनाकर उसके ढांचे को संक्रमित एवं भष्ट कर देते हैं ;

अवैध व्यापार में लिप्त व्यक्तियों को उनकी आपराधिक गतिविधियों के प्रतिफलों से वंचित करने और ऐसा करके उन आपराधिक कृत्यों को करने के उनके प्रमुख लाभ को समाप्त करने के लिए दृढ़मत होकर ;

स्वापक औषधों एवं मनः प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या के मूल कारणों, जिसमें इन औषधों एवं पदार्थों की अवैध मांग और अवैध व्यापार से अर्जित किए जाने वाले अकूत लाभ भी शामिल हैं, को निर्मूल करने की इच्छा से ;

इस बात को समझते हुए कि कुछ निश्चित पदार्थों का जिनमें कुछ प्रिकर्सर, रसायन और सॉल्वेंट शामिल हैं और जिनका प्रयोग स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थों के विनिर्माण में किया जाता है, अनुवीक्षण किए जाने के उपाय करने की जरूरत है क्योंकि इनकी सुलभता के कारण ऐसे औषध एवं पदार्थ को चोरी छिपे विनिर्माण में बढ़ोतरी हुई है ;

समुद्र के रास्ते अवैध व्यापार की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार लाने के लिए दृढ़मत होकर;

यह मानते हुए कि अवैध व्यापार का उन्मूलन करना सभी राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में समन्वित कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है ;

स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्षमता स्वीकार करते हुए और यह चाहते हुए कि ऐसे नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घटक, उसी संघ के ढांचे के अंतर्गत होने चाहिए ;

स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी क्षेत्र में विद्यमान संधियों के नीति निर्देशक सिद्धांतों और उनमें समाविष्ट नियंत्रण प्रणाली की पुनः पुष्टि करते हुए;

स्वापक औषध एकल अभिसमय, 1961; स्वापक औषध एकल अभिसमय, 1961 का 1972 के प्रोटोकोल द्वारा यथा संशोधित अभिसमय; और मनः प्रभावी पदार्थों संबंधी 1971 के अभिसमय में दिए गए उपायों को अवैध व्यापार के परिमाण और व्याप्ति का तथा इसके भयंकर परिणामों का मुकाबला करने की दृष्टि से संबंधित एवं संपूरित करने की आवश्यकता को मानते हुए ;

(अ) '1961 के यथा संशोधित अभिसमय' का अर्थ है स्वापक औषध एकल अभिसमय 1961 को 1972 के प्रोटोकोल द्वारा यथासंशोधित 'स्वापक औषध एकल अभिसमय 1961' :-

(अ) "1971 के अभिसमय" का अर्थ है मनोत्तेजक पदार्थ अभिसमय, 1971 ;

(ट) 'परिषद' का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ;

(ठ) "प्रीज कर देने" अथवा 'निरुद्ध कर देने' का अर्थ है संपत्ति के हस्तांतरण, परिवर्तन, निपटान अथवा संचलन को अस्थाई रूप से निषिद्ध करना अथवा किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर संपत्ति को अस्थाई अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में ले लेना;

(ड) "अवैध व्यापार" का अर्थ है इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 पैराग्राफ 1 एवं 2 में वर्णित अपराध;

(ढ) "स्वापक औषध" का अर्थ है स्वापक औषध एकल अभिसमय, 1961 की अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में तथा स्वापक औषध एकल अभिसमय को 1972 के प्रोटोकोल द्वारा यथा संशोधित अभिसमय में वर्णित कोई भी प्राकृतिक अथवा सिन्थेटिक पदार्थ ;

(ण) "अफीम की पोपी" का अर्थ है पापेवर सोमनीफेरम एल प्रजाति का पौधा ;

(त) "प्रतिफल" का अर्थ है अनुच्छेद 3 , पैरा 1 के अनुसार अपराध घोषित किसी कृत्य के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत अथवा प्राप्त कोई संपत्ति ;

(थ) "सम्पत्ति" का अर्थ है किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त, और ऐसी परिसंपत्तियों पर स्वत्वाधिकार अथवा हित धारिता का साक्ष्य देने वाले कानूनी दस्तावेज या लिखत ;

(य) "मनः प्रभावी" पदार्थ का अर्थ है कोई प्राकृतिक अथवा सिन्थेटिक पदार्थ, अथवा मनोत्तेजक पदार्थ अभिसमय, 1971 की अनुसूची I II III एवं IV में शामिल कोई प्राकृतिक सामग्री ;

(ध) "महासचिव" का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ;

(न) "तालिका I" एवं "तालिका II" का अर्थ है इस अभिसमय में संलग्न संख्यांकित पदार्थ सूची, अनुच्छेद 12 के अनुरूप समय समय पर यथा संशोधित ;

(प) "पारगमन राज्य" का अर्थ है वह राज्य जिसके राज्य क्षेत्र से होकर, तालिका I एवं तालिका II में शामिल अवैध स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थों को ले जाया जाता है जब कि वह राज्य इन पदार्थों का न तो मूल स्थान है और न ही इनका अंतिम गन्तव्य ।

अनुच्छेद दो अभिसमय की व्याप्ति

1. इस अभिसमय का उद्देश्य है—पक्षकारों के बीच समन्वय बढ़ाना ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय आयाम वाले स्वापक औषधों एवं मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विभिन्न पक्षों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकें। अभिसमय के अधीन अपने दायित्वों को निभाने के लिए पक्षकार, अपनी अपनी घरेलू वैधानिक प्रणालियों के मूल भूत उपबंधों के अनुरूप वैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों सहित आवश्यक उपाय करेंगे।
2. इस अभिसमय के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन पक्षकार, राज्यों को प्रभुसत्तात्मक समानता एवं राज्य क्षेत्रीय अखण्डता के और अन्य राज्यों घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न किए जाने के सिद्धांतों के अनुरूप करेंगे।
3. कोई पक्षकार ऐसे किन्हीं प्रकारों का निष्पादन तथा न्यायाधिकार का प्रयोग दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में नहीं करेगा जो कि उस अन्य पक्षकार के घरेलू कानूनों द्वारा उसके प्राधिकारियों के लिए ही अनन्य रूप से आरक्षित हैं।

अनुच्छेद तीन अपराध तथा प्रतिबंध

1. प्रत्येक पक्षकार, अपने घरेलू कानूनों के अंतर्गत निम्नलिखित कृत्यों को इरादतन किए जाने पर, इन्हें दण्डनीय अपराध घोषित कराने के लिए यथावश्यक उपाय करेगा ;

- (क) (i) 1961 के अभिसमय अथवा 1971 के अभिसमय अथवा यथासंशोधित 1961 के अभिसमय के उपबंधों के विपरीत किसी स्वापक औषध अथवा किसी मनः प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, निष्कर्षण, तैयार करना, प्रस्तुत करना, विक्री के लिए पेश करना, वितरण, विक्री किन्हीं भी शर्तों पर सुपुर्द करना, दलाली करना, परेपण करना, पारगमन परेपण करना, परिवहन, आयात या निर्यात करना ;
- (ii) अफीम की पोपी, कोका बुरा, अथवा कनाबिस पौधे की खेती, 1961 के अभिसमय और 1961 के यथासंशोधित अभिसमय के उपबंधों के विपरीत, स्वापक औषध के उत्पादन के उद्देश्य से करना ;
- (iii) उपर्युक्त (i) में वर्णित किसी भी क्रियाकलाप के उद्देश्य से किसी स्वापक औषध अथवा मनोतेजक पदार्थ को खरीदना या अपने कब्जे में रखना ;
- (iv) तालिका I एवं तालिका II में सूचीबद्ध पदार्थों का अथवा उपकरणों, सामग्री का विनिर्माण, परिवहन अथवा वितरण यह जानते हुए करना कि इनका प्रयोग स्वापक औषध अथवा मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध खेती, उत्पादन अथवा विनिर्माण में किया जाना है ;
- (v) उपर्युक्त (i)(ii)(iii) अथवा (iv) में वर्णित किसी अपराध का आयोजन, प्रबंधन अथवा वित्त पोषण करना ;
- (ख) (i) संपत्ति का परिवर्तन अथवा हस्तांतरण यह जानते हुए करना कि यह संपत्ति इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (क) के अनुसार घोषित अपराध या अपराधों से अथवा ऐसे अपराध या अपराधों में सहभागिता से प्राप्त की गई है और हस्तांतरण या परिवर्तन का उद्देश्य, संपत्ति के

746 GL/11-2

अवैध स्रोत को छिपाना या रूप परिवर्तित करना हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने का हो जो ऐसे अपराध या अपराधों को करने में लिप्त हो और अपने कृत्यों के कानूनी परिणामों से बचना चाहता हो ;

(ii) यह जानते हुए कि कोई सम्पत्ति, इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (क) के अनुसार अपराध घोषित किसी कृत्य से व्युत्पन्न हुई है या फिर ऐसे अपराध या अपराधों में सहभागिता करने से प्राप्त हुई है उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व या उसकी वास्तविक प्रकृति स्रोत, अवस्थिति, नियंत्रण संचालन, अधिकारों को छिपाना या रूप परिवर्तित करना ;

(ग) अपने सांविधिक सिद्धांतों और विधायी प्रणाली की आधारभूत संकल्पनाओं के अधीन :

(i) किसी सम्पत्ति की प्राप्ति के समय यह जानते हुए भी कि यह सम्पत्ति इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (क) के अनुसार अपराध घोषित कृत्य या कृत्यों से व्युत्पन्न हुई थी या फिर ऐसे अपराध या अपराधों में सहभागिता से प्राप्त हुई थी, उक्त सम्पत्ति का अधिग्रहण कब्जा अथवा प्रयोग करना ;

(ii) तालिका I एवं तालिका II में सूची बद्ध उपकरणों, सामग्रियों या पदार्थों को यह जानते हुए भी अपने कब्जे में रखना कि इन का प्रयोग स्वापक औषधों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध खेती, उत्पादन अथवा विनिर्माण में किया जा रहा है या किया जाना है ;

(iii) इस अनुच्छेद के अधीन अपराध घोषित किसी कृत्य को करने के लिए या स्वापक औषधों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों को अवैध रूप से प्रयोग करने के लिए दूसरों को, किसी भी साधन द्वारा सार्वजनिक रूप से उकसाना अथवा प्रेरित करना;

(iv) इस अनुच्छेद के अनुसार अपराध घोषित किसी कृत्य को करने के लिए सहायता देना, बढ़ावा देना, सुकर बनाना और परामर्श देना तथा ऐसे कृत्यों में सहभागिता करना सहयोग करना, करने के लिए षडयंत्र करना, करने के प्रयास करना;

2. अपने सांविधिक सिद्धांतों एवं अपनी विधायी प्रणाली की आधारभूत संकल्पनाओं के अधीन, प्रत्येक पक्षकार 1961 के अभिसमय, 1961 के यथासंशोधित अभिसमय अथवा 1971 के अभिसमय के उपबंधों के विपरीत स्वापक औषधों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों को वैयक्तिक उपभोग के लिए अपने कब्जे में रखने, खरीदने अथवा परिष्करण करने के कृत्य को, यदि यह कृत्य जान बूझ कर किया जाए तो, अपने घरेलू कानूनों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध घोषित करने के लिए यथावश्यक उपाय करेगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित किसी अपराध के एक आवश्यक तत्व के रूप में यथापेक्षित जानकारी, इरादे अथवा उद्देश्य को परतुपरक वास्तविक परिस्थितियों से अनुमानित किया जा सकता है ।

4(क) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार अपराध घोषित कृत्यों को प्रत्येक पक्षकार द्वारा प्रतिबंध योग्य घोषित किया जाएगा; ऐसे प्रतिबंध लगाते समय इन अपराधों की प्रकृति की गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा और ये प्रतिबंध होंगे कारावास या फिर स्वतंत्रता से वंचित करने वाले अन्य दण्ड, आर्थिक प्रतिबंध तथा जब्ती ।

(ख) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार अपराध घोषित कृत्य के लिए पक्षकार, दोषसिद्धि अथवा दण्ड के अलावा यह प्रावधान भी कर सकते हैं कि अपराधों को उपचार, शिक्षा, परवर्ती देखभाल, पुनर्वास अथवा सामाजिक पुनरेकीकरण जैसे अन्य उपायों से भी सुधारा जाएगा।

(ग) पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफों के बावजूद गौण प्रकृति के उपयुक्त मामलों में दोनों पक्ष दोषसिद्धि अथवा सजा के विकल्पों के रूप में शिक्षा, पुनर्वास अथवा सामाजिक पुनर्एकीकरण के साथ-साथ जब अपराधी नशीली दवाओं का आदि हो, तो उपचार एवं अनुरक्षण जैसी उपाय कर सकते हैं।

(घ) दोनों पक्ष दोषसिद्धि अथवा सजा के विकल्पों अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अनुसार स्थापित अपराध की दोषसिद्धि अथवा सजा के अलावा अपराधी के उपचार, शिक्षा, अनुरक्षण, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्एकीकरण के उपाय कर सकते हैं।

5. दोनों पक्ष इस बात का सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय तथा अन्य सक्षम प्राधिकरण जिनका कार्यक्षेत्र हो, वास्तविक परिस्थितियों को हिसाब में ले सकते हैं जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ के अनुसार अपराधों को करने को स्थापित करते हैं विशेषकर गम्भीर प्रकृति के जैसे :

- (क) किसी संगठित आपराधिक समूह के उस अपराध में भागीदारी जिससे अपराधी संबंध रखता है;
- (ख) अपराधी की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक गतिविधियों में भागीदारी;
- (ग) अपराधी की अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में भागीदारी जो अपराध को करने में सुविधा देते हैं;
- (घ) अपराधी द्वारा हिंसा अथवा हथियारों का प्रयोग;
- (ङ) यह तथ्य कि अपराधी सार्वजनिक पद रखता है और अपराध प्रश्नगत अपराध से सम्बद्ध है;
- (च) अवसरकों का उत्पीड़न अथवा उनका उपयोग करना;
- (छ) यह तथ्य कि अपराध पैन्ल संस्था अथवा शैक्षिक संस्थान अथवा समाज सेवा सुविधा अथवा उनके एकदम निकट अथवा उन अन्य स्थानों जहां स्कूली बच्चे और छात्र शैक्षिक, खेलकूद और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आश्रय लेते हैं;
- (ज) दोषसिद्धि से पूर्व विशेषकर उन्हीं अपराधों के लिए चाहे वह विदेशी अथवा घरेलू हो, पक्ष के घरेलू कानून के अनुमत सीमा के अन्तर्गत।

6. दोनों पक्ष इस बात का सुनिश्चय करने का प्रयास करेंगे कि इस अनुच्छेद के अनुसार स्थापित अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के संबंध में अपने-अपने घरेलू कानून के अन्तर्गत किन्हीं स्वविवेकी कानूनी शक्तियों का प्रयोग उन अपराधों के संबंध में एवं ऐसे अपराधों को करने से रोकने की आवश्यकता का उचित सम्मान करते हुए विधि प्रवर्तन उपायों की प्रभावकारिता को अधिक से अधिक बनाने के लिए किया है।

7. दोनों पक्ष इस बात का सुनिश्चय करेंगे कि वे उनके न्यायालयों अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अपराधों की गम्भीर प्रकृति तथा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर ऐसे अपराधों में सिद्धदोष व्यक्तियों की शीघ्र रिहाई अथवा पैरोल पर छोड़ने की सम्भावनाओं पर विचार करते समय ध्यान देंगे।

8. प्रत्येक पक्ष जहाँ उपयुक्त हो, अपने घरेलू कानून के अन्तर्गत सीमाओं की अवधि की एक लम्बी संविधि की स्थापना करेंगे और एक लम्बी अवधि जहाँ आरोपित अपराधी न्याय प्रशासन से बच निकला है, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित किसी अपराध के लिए कार्रवाई शुरू करेगा।
9. प्रत्येक पक्ष इस बात का सुनिश्चय करने के लिए अपनी विधिक पद्धति के अनुरूप उपयुक्त उपाय करेंगे कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराध का आरोपी अथवा सिद्धदोष व्यक्ति जो उसके प्रदेश में पाया जाता है, आवश्यक आपराधिक कार्रवाइयों के समय उपस्थित रहे।
10. विशेषकर इस अभिसमय के अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के अन्तर्गत सहयोग सहित दोनों पक्षों के बीच सहयोग के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के अनुसार स्थापित अपराधों को द्वितीय अपराध अथवा राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा अथवा दोनों पक्षों की संवैधानिक सीमाओं तथा मौलिक घरेलू कानून की पूर्वधारणा के राजनीतिक रूप से प्रेरित अपराध नहीं माना जाएगा।
11. इस अनुच्छेद में किया गया कोई भी उल्लेख इस सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करेगा कि उन अपराधों का विवरण जिसका वह उल्लेख करता है तथा जो उसके कानूनी रक्षा का है, किसी पक्ष के घरेलू कानून के लिए आरक्षित है और इस प्रकार के अपराध में उक्त कानून के अनुरूप मुकदमा चलाया जाएगा तथा सजा दी जाएगी।

अनुच्छेद - चार क्षेत्राधिकार

1. प्रत्येक पक्ष
- (क) ऐसे उपाय करेगा जो अनुच्छेद-तीन के पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के बारे में उसके क्षेत्राधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, जब :
- (i) अपराध उसके प्रदेश में किया जाता है;
- (ii) अपराध उस जहाज अथवा हवाई जहाज में किया जाता है जिस पर उसका झण्डा फहरा रहा हो जो अपराध को करते समय उसके कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हो;
- (ख) ऐसे उपाय कर सकता है जो अनुच्छेद-तीन के पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के बारे में उसके क्षेत्राधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो; जब
- (i) अपराध उसके किसी राष्ट्रिक अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका उसके प्रदेश में स्थायी आवास हो;
- (ii) अपराध ऐसे जहाज में किया जाता है जिसके संबंध में उक्त पक्ष को अनुच्छेद-सत्रह के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, बशर्ते कि इस प्रकार का क्षेत्राधिकार केवल उक्त अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 और 9 में उल्लिखित करारों अथवा व्यवस्थाओं के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा ;

(iii) अपराध अनुच्छेद-तीन के पैराग्राफ 1, उप पैराग्राफ (ग) (iv) के अनुसार स्थापित अपराधों में से एक है, और अनुच्छेद-तीन के पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराध उसके प्रदेश के भीतर करने के उद्देश्य से उसके प्रदेश के बाहर किया जाता है।

2. प्रत्येक पक्ष

(क) जब आरोपित अपराधी उसके प्रदेश में उपस्थित हो और वह निम्नलिखित आधारों पर अन्य पक्ष को उसे प्रत्यर्पित नहीं करता है तो अनुच्छेद-तीन पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के संबंध में उसके क्षेत्राधिकार को स्थापित करने के लिए भी ऐसे उपाय करेगा जो उसके लिए आवश्यक हो :

(i) यह कि अपराध उसके प्रदेश में किया गया हो अथवा उस जहाज अथवा हवाई जहाज में किया गया हो जिस पर उसका झण्डा फहरा रहा हो जो अपराध को करते समय उसके कानून के अंतर्गत पंजीकृत था;

(ii) यह कि अपराध उसके राष्ट्रियों में से किसी एक राष्ट्रिक ने किया हो।

(ख) जब आरोपित अपराधी उसके प्रदेश में हो और वह उसे अन्य पक्ष को प्रत्यर्पित नहीं करता हो तो अनुच्छेद - तीन के पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के संबंध में अपना क्षेत्राधिकार स्थापित करने के लिए ऐसे उपाय करे जो आवश्यक हो सकते हैं।

3. यह अभिसमय किसी पक्ष को उसके घरेलू कानून के अनुसार स्थापित किसी आपराधिक क्षेत्राधिकार की कार्यवाही को अलग नहीं करता है।

अनुच्छेद - पांच समपहरण

1. समपहरण के लिए प्रत्येक पक्ष ऐसे उपाय अपनाएगा जो आवश्यक हो सकते हैं:

(क) अनुच्छेद-तीन, पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराधों से प्राप्त अर्थागम अथवा सम्पत्ति जिसकी कीमत ऐसे अर्थागम के सदृश हो;

(ख) अनुच्छेद-तीन, पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराधों में प्रयुक्त स्वापकों तथा मनः प्रभावी पदार्थों, सामग्रियों एवं उपकरण अथवा अन्य सहायता अथवा उन्हें किसी पद्धति में प्रयोग में लाने की मंशा;

2. प्रत्येक पक्ष ऐसे उपाय भी करेगा जो उसके सक्षम प्राधिकारियों के लिए सम्भावित समपहरण के प्रयोजनार्थ अर्थागम, सम्पत्ति, सहायता, अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में उल्लिखित अन्य वस्तुओं की पहचान करने, जांच करने तथा रोक लगाने अथवा जब्त करने के लिए आवश्यक हों।

3. इस अनुच्छेद में उल्लिखित उपायों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक पक्ष अपने न्यायालयों अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणों को यह आदेश करने के लिए समर्थ करेगा कि बैंक, वित्तीय अथवा वाणिज्यिक बिक्री को उपलब्ध कराया जाए अथवा जप्त किया जाए। कोई भी पक्ष इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक गुप्तता के आधार पर कार्य करने से अधिकार नहीं करेगा।

4. (क) अनुच्छेद-तीन, पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित किसी अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार होने पर अन्य पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार अनुरोध करने पर वह पक्ष जिसके क्षेत्राधिकार में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अर्थागम, सम्पत्ति, सहायता अथवा अन्य कोई वस्तु अवस्थित है;
- (i) समपहरण का आदेश प्राप्त करने के लिए उसके सक्षम प्राधिकारियों को अनुरोध प्रस्तुत करेगा तथा यदि ऐसा मंजूर किया जाता है तो वह उसे कार्यान्वित करेगा; अथवा
- (ii) अनुरोध की गई सीमा तक उसे कार्यान्वित करने के लिए उसके सक्षम प्राधिकारियों को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जारी समपहरण का आदेश प्रस्तुत करेगा जहां तक यह अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में अवस्थित पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अर्थागम, सम्पत्ति, सहायता अथवा अन्य किसी वस्तु से है।
- (ख) अनुच्छेद-तीन, पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित किसी अपराध के संबंध में किसी अन्य पक्ष जिसका उस पर क्षेत्राधिकार है, द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार अनुरोध करने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष के आदेश पर अथवा इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के अनुसार सम्भावित समपहरण के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अर्थागम, सम्पत्ति, सहायता अथवा किसी अन्य वस्तु की पहचान, जांच तथा रोक लगाने अथवा जब्ती के उपाय करेगा।
- (ग) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में लिए गए निर्णयों अथवा की गई कार्रवाईयों को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा अपने घरेलू कानूनों, अपने क्रियाविधिक नियमों अथवा किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संधि, करार अथवा उस व्यवस्था जिसमें वह अनुरोधकर्ता पक्ष के संबंध में बाध्य है, के अनुसार तथा उनके प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
- (घ) अनुच्छेद-सात, पैराग्राफ 6 से 19 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू हैं। अनुच्छेद-सात, पैराग्राफ-10 में उल्लिखित सूचना के अलावा इस अनुच्छेद के अनुसरण में किए गए अनुरोधों में निम्नलिखित शामिल होगा :
- (i) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) (i) से संबंधित अनुरोध के मामले में समपहरण की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण और अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जिन तथ्यों के विवरण पर विश्वास किया गया है, को उसके घरेलू कानून के अंतर्गत आदेश प्राप्त करने के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष पर्याप्त मानता है;
- (ii) उप-पैराग्राफ (क) (ii) से संबंधित अनुरोध के मामले में अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जारी समपहरण के आदेश की विधिवत अनुमेय प्रति जिस पर अनुरोध आधारित है, तथ्यों का विवरण और सूचना जिसके संबंध में आदेश के निष्पादन का अनुरोध किया है;
- (iii) उप-पैराग्राफ (ख) से संबंधित अनुरोध के मामले में अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जिस पर भरोसा किया गया है उन तथ्यों का विवरण और अनुरोध की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा।
- (ङ) प्रत्येक पक्ष महासचिव को अपने उन कानूनों तथा विनियमों के पाठ की प्रति भेजेगा जो इस पैराग्राफ को कार्यान्वित करते हैं और ऐसे कानूनों तथा विनियमों में अनुवर्ती किन्हीं परिवर्तनों के पाठ की प्रति।

(च) यदि कोई पक्ष इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में उल्लिखित उपायों को करने का निर्णय लेता है जो संगत संधि की मौजूदगी की शर्त पर है तो उक्त पक्ष इस अभिसमय को आवश्यक एवं पर्याप्त संधि आधार के रूप में विचार करेगा।

(छ) दोनों पक्ष इस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संधियाँ, करार अथवा प्रवन्ध करना चाहेंगी।

5. (क) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 अथवा पैराग्राफ 4 के अनुसार समपहरित अर्थागम अथवा सम्पत्ति उक्त पक्ष द्वारा अपने घरेलू कानून और प्रशासनिक क्रियाविधियों के अनुसार निपटायी जाएगी।

(ख) इस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पक्ष के अनुरोध पर कार्यवाही करते समय कोई भी पक्ष निम्नलिखित के संबंध में करारों को सम्पन्न करने के संबंध में विशेष ध्यान दे सकता है :

(i) ऐसे अर्थागम तथा सम्पत्ति की कीमत, अथवा ऐसे अर्थागम अथवा सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त निधियों अथवा उसके पर्याप्त भाग को स्वायत्त और मनः प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी तथा दुरुपयोग का सामना करने वाले विशेषज्ञ अन्तर-सरकारी निकायों को अंशदान करना;

(ii) ऐसे अर्थागम तथा सम्पत्ति, अथवा ऐसे अर्थागम अथवा सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त निधियों को नियमित तौर पर अथवा मामला-दर-मामला आधार पर अपने घरेलू कानून, प्रशासनिक क्रियाविधियों अथवा इस प्रयोजनार्थ सम्पन्न द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करारों के अनुसार अन्य पक्षों के साथ बांटना;

6. (क) यदि अर्थागम को अन्य सम्पत्ति में परिवर्तित अथवा बदल दिया गया है तो ऐसी सम्पत्ति अर्थागम के बजाय इस अनुच्छेद में उल्लिखित उपायों के अधीन होगी।

(ख) यदि अर्थागम को वैध स्रोतों से अर्जित सम्पत्ति के साथ मिला लिया गया है तो सम्पत्ति को जब्ती अथवा रोक लगाने से संबंधित किसी अधिकार के बावजूद शामिल किए गए अर्थागम की कीमत का आकलन करके समपहरण किया जाएगा।

(ग) निम्नलिखित से प्राप्त आय अथवा अन्य लाभ:

(i) अर्थागम;

(ii) वह सम्पत्ति जिसमें अर्थागम को लगाया अथवा बदला गया है; अथवा

(iii) वह सम्पत्ति जिसमें अर्थागम को शामिल किया गया है, इस अनुच्छेद में उल्लिखित उपायों के अंतर्गत उसी पद्धति और उसी सीमा तक अधीन होगी जिस सीमा तक अर्थागम होगा।

7. प्रत्येक पक्ष इस बात का सुनिश्चय करने के लिए समपहरण के योग्य आरोधित अर्थागम अन्य सम्पत्ति के कानूनी उद्भव के बारे में साक्ष्य के दायित्व का उसी सीमा तक सुनिश्चय करने पर विचार कर सकता है कि इस प्रकार की कार्रवाई उसके घरेलू कानूनों के सिद्धान्तों तथा न्यायिक एवं अन्य कार्यवाहियों के अनुरूप हो।

8. इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अर्थ तीसरे पक्षों के वास्तविक अधिकारों के प्रतिकूल नहीं लगाया जाएगा ।

9. इस अनुच्छेद में उल्लिखित कुछ भी इस सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करेगा कि वे उपाय जिनका इसमें उल्लेख है, को उस पक्ष के घरेलू कानून के अनुसार तथा उसके प्रावधानों के अधधीन परिभाषित किया जाएगा तथा कार्यान्वित किया जाएगा ।

अनुच्छेद - छह प्रत्यर्पण

1. यह अनुच्छेद दोनों पक्षों द्वारा अनुच्छेद-तीन, पैराग्राफ 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के लिए लागू होगा ।
2. इन अपराधों में से प्रत्येक अपराध जिनके संबंध में यह अनुच्छेद लागू होता है, को दोनों पक्षों के बीच मौजूद किसी प्रत्यर्पण संधि में एक प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में शामिल किया हुआ समझा जाएगा । दोनों पक्ष उनके बीच सम्पन्न प्रत्येक प्रत्यर्पण संधि में ऐसे अपराधों को प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में शामिल करने का वचन लेते हैं ।
3. यदि कोई पक्ष किसी संधि की मौजूदगी में प्रत्यर्पण को शर्त मानता है, उस अन्य पक्ष से प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त करता है जिसके साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो वह किसी अपराध जिस पर यह अनुच्छेद लागू होता है, के संबंध में प्रत्यर्पण के लिए इस अभिसमय को प्रत्यर्पण के लिए एक कानूनी आधार पर विचार कर सकता है । वे पक्ष जो प्रत्यर्पण के लिए इस अभिसमय का उपयोग करने के उद्देश्य से विस्तृत विधान चाहते हैं, ऐसे विधान के अधिनियम पर विचार करेंगे जो आवश्यक हो ।
4. वे पक्ष किसी संधि की मौजूदगी में प्रत्यर्पण को शर्त नहीं मनाते हैं, को उन अपराधों को मान्यता देंगे जिनके संबंध में यह अनुच्छेद उनके बीच एक प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में लागू होता है ।
5. प्रत्यर्पण अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून द्वारा की गई शर्तों अथवा अनुमेय प्रत्यर्पण संधियों सहित उन आधारों पर जिनके आधार पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष प्रत्यर्पण से इन्कार कर सकता है, के अधधीन होगा ।
6. इस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते समय अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष ऐसे अनुरोधों का अनुपालन करने से इन्कार कर सकता है जहां उसके न्यायिक अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारियों को आगे बढ़ने के लिए विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि इसके अनुपालन से उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनीतिक मत की वजह से किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने अथवा सजा देने में सुविधा होगी अथवा इस अनुरोध द्वारा किसी व्यक्ति को उन कारणों से किसी कारण से प्रतिकूल नहीं पड़ेगा ।
7. दोनों पक्ष प्रत्यर्पण क्रियाविधियों को शीघ्र पूरा करने तथा उस किसी अपराध जिसके संबंध में यह अनुच्छेद लागू होता है, की सम्भावित आवश्यकताओं को सरल बनाने का प्रयास करेंगे ।
8. उसके घरेलू कानून और उसकी प्रत्यर्पण संधियों के प्रावधानों के अधधीन अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस बात से सन्तुष्ट होते हुए कि उचित परिस्थितियां आवश्यक है और अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है और जो उसके प्रदेश में हिरासत में उपस्थित है, उस व्यक्ति को ले जा सकता है अथवा प्रत्यर्पण की कार्यवाहियों के लिए उसकी उपस्थिति का सुनिश्चय करने के लिए अन्य उपाय कर सकता है ।

अपने घरेलू कानून के अनुसार घोषित आपराधिक न्यायाधिकार के प्रयोग के प्रति निष्पक्षता रखते हुए जिरा पक्षकार के क्षेत्र में तथाकथित अपराधी पाया जाता है वह क अनुच्छेद 4, पैरा 2 उप पैरा क में निहित आधारों पर अनुच्छेद 3, पैरा 1 के अनुसार घोषित किसी अपराध के संबंध में यदि वह उसका प्रत्यर्पण नहीं करता तो वह अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी सक्षम अधिकारी के पास मुकदमा दर्ज करेगा जब तक कि अनुरोध कर्ता पक्ष कार के साथ अन्यथा सहमत नहीं हो ।

(ख) यदि वह इस प्रकार के अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण नहीं करता और अनुच्छेद 4, पैरा 2 उप पैरा ख के अनुसार उस अपराध के संबंध में न्यायाधिकार घोषित कर चुका है तो वह अभियोजन के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास मुकदमा दर्ज करेगा जब तक कि उसके वैध न्यायाधिकार के संरक्षण हेतु अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा अन्यथा का अनुरोध न किया गया हो ।

10. यदि दण्ड लागू करने के प्रयोजन से अपेक्षित प्रत्यर्पण से इस कारण वश इंकार कर दिया जाता है कि अपेक्षित व्यक्ति अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार का राष्ट्रिक है, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार के आवेदन पर यदि उसका कानून मंजूरी दे और इस प्रकार के कानून की अपेक्षाओं के अनुरूप अनुरोधकर्ता पक्षकार आवेदन पर अनुरोध कर्ता पक्षकार के कानून के तहत लगाए गए दण्ड को अथवा बाकी बचे दण्ड को लागू करने पर विचार करेगा ।

11. पक्षकार प्रत्यर्पण को निष्पादित करने अथवा उसकी प्रभाविता के संवर्द्धन हेतु द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते संपन्न करने का प्रयास करेंगे ।

12. पक्षकार उन अपराधों के लिए जिन पर यह समझौता लागू होता है, उन व्यक्तियों के स्थानांतरण पर जिन्हें कैद और स्वतंत्रता से वंचित करने वाले अन्य दण्ड दिए गए हों, तदर्थ अथवा सामान्य द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौतों को अंजाम देने पर विचार करेंगे ताकि वे अपराधी वहां अपने दंड पूरे करें ।

अनुच्छेद सात पारस्परिक विधिक सहायता

इस अनुच्छेद के अनुपालन में पक्षकार अनुच्छेद 3 पैरा 1 के अनुरूप घोषित आपराधिक कृत्यों के संबंध में जांच, अभियोजनों और न्यायिक कार्रवाइयों में यथा संभव पारस्परिक विधिक सहायता एक दूसरे को प्रदान करेंगे ।

2. इस अनुच्छेद के अनुसार पारस्परिक विधिक सहायता का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है :

क) व्यक्तियों से साक्ष्य अथवा वक्तव्य लेना ;

ख) न्यायिक प्रलेख देना ;

746 GI/11-4

- ग) खोज और जवाब करना
 - घ) वस्तुओं और स्थलों की जांच करना ।
 - ङ) सूचना आर साक्ष्य वस्तुओं को प्रदान करना ;
 - च) बैंक, वित्तीय, कॉर्पोरेट अथवा व्यापारिक रिकार्डों सहित संगत दस्तावेजों और रिकार्डों की मूल अथवा प्रमाणीकृत प्रतियां प्रदान करना ;
 - छ) साक्ष्य प्रयोजनों के लिए आय, संपत्ति साधनों अथवा अन्य वस्तुओं की पहचान अथवा उनको खोजना ।
3. पक्षकार एक दूसरे के लिए किसी भी प्रकार की पारस्परिक विधिक सहायता का वहन कर सकते हैं जो कि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के घरेलू कानून द्वारा अनुमत्य हो ।
4. अनुरोध पर पक्षकार घरेलू कानून और पद्धति के अनुरूप गिरफ्तार व्यक्तियों सहित ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा उपलब्धता की व्यवस्था करेंगे अथवा प्रोत्साहित करेंगे जो जांच में सहायता अथवा कार्यवाहियों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करें ।
5. कोई पक्षकार बैंक गोपनीयता के आधार पर इस अनुच्छेद के तहत पारस्परिक विधिक सहायता प्रदान करने से इंकार नहीं करेगा ।
6. इस अनुच्छेद के प्रावधान किसी अन्य द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संधि के अंतर्गत आने वाली बाधकताओं को प्रभावित नहीं करेंगे जो कि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता को शासित करती हो अथवा करे ।
7. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 8 से 19 इस अनुच्छेद के अनुपालन में किए गए अनुरोधों पर लागू होंगे यदि प्रश्नगत पक्षकार पारस्परिक विधिक सहायता संधि द्वारा बंधे हुए नहीं हों । यदि ये पक्षकार इस प्रकार की संधि द्वारा बंधे हुए हों तो उस संधि के अनुरूप प्रावधान लागू होंगे जब तक कि पक्षकार उसके एवज में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 8 से 19 लागू करने में अपनी सहमति व्यक्त नहीं करते ।
8. पक्षकार प्राधिकारी अथवा आवश्यक होने पर प्राधिकारियों को नामोद्दिष्ट करेंगे जिनके पास पारस्परिक विधिक सहायता हेतु अनुरोधों के निष्पादन अथवा उन्हें निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारियों को अंतरित करने का उत्तर दायित्व और शक्ति होगी । इस प्रयाजन के लिए नामोद्दिष्ट प्राधिकारी महासचिव को अधिसूचित किए जाएंगे । पारस्परिक विधिक सहायता के लिए अनुरोधों का अंतरण और उससे संबंधित कोई संचार पक्षकारों द्वारा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के बीच किया जाएगा; इस अपेक्षा से किसी पक्षकार को इस मांग का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा कि इस प्रकार के अनुरोध

और संचार उसे राजनायिक चैनल के माध्यम से किए जाएं और अति तत्कालिक परिस्थितियों में जहां पक्षकार सहमत हों, यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के चैनलों के माध्यम से किए जाएं ।

9. अनुरोध लिखित रूप में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को स्वीकार्य भाषा में किए जाएंगे । प्रत्येक पक्षकार को स्वीकार्य भाषा अथवा भाषाएं महासचिव को अधिसूचित की जाएंगी । अति तत्कालिक परिस्थितियों में जहां पक्षकार सहमत हों, अनुरोधों को मौखिक रूप से किया जा सकता है, किंतु उसके पश्चात् उनकी पुष्टि लिखित रूप में की जाएगी ।

10. पारस्परिक विधिक सहायता के अनुरोध में निम्नलिखित होगा :

- (क) अनुरोध करने वाले प्राधिकारी की पहचान ;
- (ख) अनुरोध से संबंधित जांच, अभियोजन अथवा कार्यवाही का विषय और प्रकृति और इस प्रकार की जांच, अभियोजन तथा कार्यवाही को अंजाम देने वाले प्राधिकारी का नाम और कार्य ;
- (ग) न्यायिक प्रलेखों की तामील के प्रयोजन से संबंधित अनुरोध को छोड़ते हुए संगत तथ्यों का सारांश ;
- (घ) अपेक्षित सहायता के ब्यौरे और किसी प्रक्रिया विशेष के ब्यौरे जिसका अनुपालन अनुरोधकर्ता पक्षकार करवाना चाहता हो ;
- (ङ) जहां संभव हो, संबंधित किसी व्यक्ति की पहचान, अवस्थिति और राष्ट्रीयता ;
- (च) वह प्रयोजन जिसके लिए साक्ष्य, सूचना अथवा कार्यवाई अपेक्षित हो ।

11. अनुरोधकर्ता पक्षकार अपने घरेलू कानून के अनुसार अथवा जब इस प्रकार का निष्पादन सुविधाजनक हो, अनुरोध के निष्पादन हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाली अतिरिक्त सूचना काक अनुरोध कर सकता है ।

12. अनुरोध का निष्पादन अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के घरेलू कानून के अनुसार किया जाएगा और उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के घरेलू कानून का उल्लंघन नहीं हो तथा जहां तक संभव हो, अनुरोध में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जाएगा ।

13. अनुरोधकर्ता पक्षकार अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना अथवा साक्ष्य का प्रयोग अथवा प्रेषण अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की पूर्व अनुमति के बिना अनुरोध में उल्लिखित जांचों, अभियोजनों अथवा कार्यवाहियों के अलावा अन्य जांचों, अभियोजनों अथवा कार्यवाहियों के लिए नहीं करेगा ।

14. अनुरोधकर्ता पक्षकार अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार से यह अपेक्षा रख सकती है कि वह अनुरोध के निष्पादन हेतु आवश्यक सीमा तक अनुरोध के तथ्य और विषय सामग्री को गोपनीय रखे। यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार गोपनीयता की अपेक्षा को पूरा नहीं कर सके तो अनुरोधकर्ता पक्षकार को तत्काल इसकी सूचना देगा।
15. पारस्परिक विधिक सहायता से इंकार किया जा सकता है :
- क) यदि अनुरोध इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया हो ;
- ख) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार यह मानता हो कि अनुरोध के निष्पादन से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा, अन्य सार्वजनिक अथवा अनिवार्य हितों को हानि पहुंच सकती है ;
- ग) यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के प्राधिकारियों को अपने घरेलू कानून द्वारा इसी प्रकार के किसी अन्य अपराध के संबंध में कार्रवाई करने से प्रतिबंधित किया गया हो जिसकी यदि स्वयं अपने न्यायाधिकार के तहत जांच अभियोजन अथवा कार्यवाही की गई हो ;
- घ) यदि वह अपेक्षित अनुरोध के लिए पारस्परिक विधिक सहायता के संबंध में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की विधिक प्रणाली का उल्लंघन।
16. पारस्परिक विधिक सहायता से इंकार करने के कारण दिए जाएंगे।
17. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा पारस्परिक विधिक सहायता इस आधार पर मुत्तवी किया जा सकती है कि वह जारी जांच, अभियोजन अथवा कार्रवाइयों में रुकावट उत्पन्न कर रही हों। ऐसे मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार के साथ यह निर्धारित करने के लिए परामर्श करेगा कि क्या अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों पर सहायता इसके बावजूद प्रदान की जा सकती है, अथवा नहीं।
18. एक गवाह विशेषज्ञ अथवा अन्य व्यक्ति को जो अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में किसी कार्रवाइ में साक्ष्य देने अथवा किसी जांच, अभियोजन अथवा न्यायिक कार्रवाई में सहायता करने की सहमति व्यक्त करे, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र से उसके प्रस्थान से पूर्व कार्यो ; चूको अथवा दोषसिद्धि के संबंध में उस क्षेत्र में अभियोजित, कैद, दण्डित नहीं किया जाएगा अथवा उसकी निजी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार का सुरक्षित आचरण समाप्त हो जाएगा जब गवाह, विशेषज्ञ और अन्यव्यक्ति प्राधिकारियों द्वारा यह सूचित किए जाने की तारीख से लगातार 15 दिन अथवा पक्षकारों द्वारा सहमत अवधि बीत जाने तक कि अब उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, उसके पास लौटने का अवसर है, वह फिर भी स्वेच्छा से उस क्षेत्र में है, जाने के बाद फिर स्वयं अपनी इच्छा से लौट आया हो।

19. किसी अनुरोध के निष्पादन की सामान्य लागतों का भुगतान अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा किया जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षकारों द्वारा अन्यथा पर सहमति नहीं व्यक्त की गई हो। यदि अनुरोध की पूर्ति हेतु पर्याप्त अथवा असामान्य प्रकृति के व्यय हों अथवा करने अपेक्षित हो तो दोनों पक्ष उन शर्तों के निर्धारण हेतु परामर्श करेंगे जिनके तहत अनुरोध का निष्पादन किया जाएगा तथा यह भी कि लागत का वहन किस प्रकार होगा।

20. पक्षकार यथा आवश्यकता उन द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौतों अथवा व्यवस्थाओं की संभावनाओं पर विचार करेंगे जो इस अनुच्छेद के प्रावधानों को व्यावहारिक रूप से लागू करने अथवा उनके संवर्द्धन का प्रयोजन सिद्ध करे।

अनुच्छेद आठ कार्यवाइयों का अंतरण

दोनों पक्षकार उन मामलों में अनुच्छेद 3, पैराग्राफ 1 के अनुरूप घोषित आपराधिक अभियोजन के अपराधों के लिए कार्यवाहियों को एक दूसरे को अंतरित करने पर विचार कर सकते हैं जिन मामलों में इस प्रकार के अंतरण को उपयुक्त न्याय प्रशासन के हित में माना जाए।

अनुच्छेद नौ सहयोग और प्रशिक्षण के अन्य स्वरूप

1. पक्षकार अनुच्छेद 3, पैराग्राफ 1 के अनुसार घोषित आपराधिक कृत्यों को दबाने और कानून लागू करने की प्रभाविता के संवर्द्धन के दृष्टिकोण से अपनी अपनी घरेलू विधिक और प्राशासनिक प्रणालियों के अनुरूप एक दूसरे के साथ निकटता से सहयोग करेंगे। वे विशेषकर द्विपक्षीय अथवा बहु पक्षीय समझौतों अथवा व्यवस्थाओं के आधार पर :

क) सूचना के सुरक्षित और द्रुत आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी सक्षम एजेंसियों और सेवाओं के बीच संचार चैनल स्थापित करेंगे और उनका अनुरक्षण करेंगे। यदि संबंधित पक्षकार इसे उपयुक्त माने, अन्य आपराधिक गतिविधियों के साथ संपर्क को शामिल करते हुए अनुच्छेद 3 पैराग्राफ 1 अनुरूप स्थापित अपराधों के सभी पक्षों के संबंध में ;

ख) अनुच्छेद 3 पैराग्राफ 1 के अनुरूप स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के अपराधों के संबंध में जांच करने में एक दूसरे के साथ निम्नलिखित से संबंधित सहयोग :

(i) अनुच्छेद 3 पैराग्राफ 1 के अनुरूप स्थापित अपराधों में शामिल होने के शक वाले व्यक्तियों की पहचान, अवस्थिति और गतिविधियां ;

(ii) इस प्रकार के अपराधों से प्राप्त आय अथवा संपत्ति संबंधित गतिविधियां ;

746 GI/11-5

(iii) इस अभिसमय की सारणी 1 और सारणी 2 में नशीले पदार्थों, स्वापकों, पदार्थों की गतिविधि और इस प्रकार के अपराधों में प्रयुक्त अथवा प्रयोग के आशय वाले साधन ;

ग) उचित मामलों में, और यदि वह घरेलू कानून का उल्लंघन नहीं हो तो इस पैराग्राफ के प्रावधानों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों और आपरेशनों की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त दल स्थापित करें। इस प्रकार दलों में भाग लेने वाले किसी पक्षकार के अधिकर्मी उस पक्षकार के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत के तौर पर कार्य करेंगे जिस पक्षकार के क्षेत्र में कार्यवाही को अंजाम दिया जाना है ; इस प्रकार के सभी मामलों में शामिल पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस पक्षकार के क्षेत्र में कार्यवाही की जानी है उस पक्षकार की संप्रभुता का पूर्ण आदर हो ;

घ) उपयुक्त होने पर विलेषणात्मक अथवा जांच प्रयोजनों के लिए पदार्थों की आवश्यक मात्रा प्रदान करे ;

ड.) उनकी सक्षम एजेंसियों और सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वयन की व्यवस्था करें और जन संपर्क अधिकारियों की तैनाती सहित कार्मिकों और अन्य विशेषज्ञों के आदान प्रदान को बढ़ावा दें।

2. प्रत्येक पक्षकार यथा आवश्यकता सीमाशुल्क सहित अपने कानून प्रवर्तन और अन्य कार्मिकों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ, विकसित करेगा अथवा उनमें सुधार लाएगा जिनमें अनुच्छेद 3 पैराग्राफ 1 के अनुरूप स्थापित अपराधों को दवाना शामिल है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में विशेषरूप से निम्नलिखित शामिल होगा :

क) अनुच्छेद 3 पैराग्राफ 1 के अनुरूप अपराधों का पता लगाना और उन्हें दवाना ;

ख) अनुच्छेद 3 पैराग्राफ 1 के अनुरूप स्थापित अपराधों में संलिप्त होने के शक वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त मार्ग और तकनीकें विशेषकर ट्रांजिट राज्यों में, और उपयुक्तरोधी उपाय ;

ग) नशीले पदार्थों, स्वापकों और सारणी 1 और 2 में निहित पदार्थों के आयात और निर्यात की निगरानी ;

(घ) इससे प्राप्त आय तथा सम्पत्ति, और औषध द्रव्यों, मनः प्रभावी पदार्थों और तालिका-1 एवं तालिका-11 में दिए गए पदार्थों तथा इसमें प्रयुक्त अथवा प्रयुक्त किए जाने की मंशा वाले हथियारों, अनुच्छेद-3, पैराग्राफ-1 के अनुसार स्थापित के अनुसार स्थापित अपराधों को प्रारम्भ करने की खोज करना और उसे मॉनीटर करना;

(ङ) ऐसी आय, सम्पत्ति तथा हथियारों के अन्तरण, गुप्त रखने तथा छिपाने के लिए प्रयुक्त तरीके;

(च) साक्ष्यों का संग्रहण;

(छ) मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा मुक्त बन्दरगाहों पर नियंत्रण तकनीक;

(ज) नए नियम प्रवर्तन तकनीक;

3. पक्षकार, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ -2 में संदर्भित क्षेत्रों में प्राप्त विशेषज्ञता के लिए तैयार किए गए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना तथा कार्यान्वयन को एक-दूसरे के साथ बाटने में सहयोग करेंगे और इसके लिए, जब भी उपयुक्त होगा, परस्पर हित-चिन्ताओं से सम्बद्ध समस्याओं को मार्गस्थ राज्यों की विशेष समस्याओं तथा आवश्यकताओं सहित सहयोग और प्रेरक विचारों को संवर्द्धित करने के लिए क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संगोष्ठियां करेंगे ।

अनुच्छेद - दस

मार्गस्थ राज्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायता

दोनों पक्षकार मार्गस्थ राज्यों की सहायता और समर्थन के लिए सीधे अथवा सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से, विशेषरूप से ऐसी सहायता और आवश्यकता वाले विकासशील देशों के लिए यथासम्भव निधेवादेश तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों पर तकनीकी सहयोग के कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग करेंगे ।

2. दोनों पक्षकार सीधे अथवा सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से अवैध व्यापार को रोकने तथा उसके प्रभावकारी नियंत्रण के लिए आवश्यक आधारसंरचना को संवर्द्धित तथा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऐसे मार्गमन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ।

3. दोनों पक्षकार इस अनुच्छेद के अनुपालन में द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संधियां सम्पन्न करेंगे अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावकारिता को संवर्द्धित करने की व्यवस्था करेंगे तथा इस सम्बन्ध में वित्तीय प्रबन्धों को ध्यान में रखेंगे ।

अनुच्छेद - ग्यारह

नियंत्रित सुपुर्दगी

1. दोनों पक्षकार अनुच्छेद-तीन पैराग्राफ-1 के अनुसार स्थापित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित सुपुर्दगी के उपयुक्त प्रयोग के लिए अनुमति देने के लिए, यदि उनकी अपनी-अपनी वैधानिक व्यवस्थाओं के आधारभूत सिद्धान्तों द्वारा अनुमत्त होगा, अपनी संभाव्यताओं के भीतर आवश्यक उपाय करेंगे ।

2. नियंत्रित सुपुर्दगी के प्रयोग का निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा और जब आवश्यक होगा, संबंधित पक्षों द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के मामले में समझबूझ तथा वित्तीय प्रबन्धों को ध्यान में रखा जाएगा।

3. अवैध प्रेषण, जिनकी नियंत्रित सुपुर्दगी करने की सहमति हुई है, संबंधित पक्षकारों की सहमति से अवरूद्ध कर दिया जाएगा अथवा औषध द्रव्यों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों को उसी प्रकार अथवा हटा कर अथवा पूरा या खण्डों में बदलने की अनुमति दी जाएगी।

अनुच्छेद - बारह

औषध द्रव्यों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण में लगातार प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ

1. दोनों पक्षकार अवैध औषधों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण के उद्देश्य से तालिका-1 और तालिका-11 में वर्णित पदार्थों को रखने जाने से रोकने के लिए जो उचित समझे उपाय करेंगे और इसके लिए एक-दूसरे को सहयोग करेंगे।

2. यदि एक पक्ष अथवा बोर्ड के पास सूचना है जो उनके मत से, तालिका-1 अथवा तालिका-11 के पदार्थ में संविष्ट होनी चाहिए तो उसे महासचिव को सूचित किया जाएगा और उस अधिसूचना के समर्थन में उसे सूचना भेजी जाएगी। इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-2 से 7 में निर्धारित प्रक्रिया तब भी लागू होगी जब एक पक्ष अथवा बोर्ड के पास तालिका-1 अथवा तालिका-11 से पदार्थ के हटाने अथवा एक तालिका से दूसरी तालिका में पदार्थ के अन्तरण के लिए तर्कसंगत सूचना होगी।

3. महासचिव, ऐसी अधिसूचना, और अन्य सूचना जिसे वह संगत समझता है, पक्षकारों को, आयोग को देगा और जहां अधिसूचना पक्षकार द्वारा दी गई हो, बोर्ड को देगा। पक्षकार अधिसूचना से सम्बद्ध अपनी टिप्पणियां, सभी अनुपूरक सूचना के साथ महासचिव को देंगे, जिससे बोर्ड को आंकलन करने में और आयोग को निर्णय पर पहुंचने में सहायता मिलेगी।

4. यदि बोर्ड, औषध द्रव्यों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों का वैध उद्देश्यों तथा अवैध निर्माण दोनों में पदार्थों के वैध उपयोग की मात्रा, महत्व और विविधता अथवा पदार्थों के वैकल्पिक प्रयोग की सम्भावना तथा सुगमता को ध्यान में रखते हुए यह पाता है ;

(क) कि पदार्थ का औषध द्रव्य अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण में लगातार उपयोग हो रहा है।

(ख) कि अवैध औषध अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण का परिमाण और मात्रा जन स्वास्थ्य अथवा सामाजिक समस्याओं के लिए गम्भीर समस्याएं उत्पन्न करती है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के वारंट के लिए, इसे आयोग को सूचित किया जाएगा जिसमें पदार्थ के आकलन में उसके वैध प्रयोग और अवैध निर्माण दोनों को या तो तालिका-1 अथवा तालिका-11 में जोड़ने से होने वाले प्रभाव सहित यदि कोई है, तो उसके आकलन में प्रयुक्त होने वाले मॉनीटरिंग उपायों की सिफारिशों सहित शामिल किया जाएगा;

5. आयोग, दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां तथा बोर्ड, जिसका आकलन वैज्ञानिक मामलों में निर्धारक होगा, की टिप्पणियों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, तथा अन्य, किसी सम्बद्ध तथ्य को उचित ध्यान देते हुए, उसके सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पदार्थ को तालिका-1 अथवा तालिका-11 में रखने का निर्णय लेगा।

6. इस अनुच्छेद के अनुपालन में आयोग द्वारा लिया गया कोई निर्णय, महासचिव द्वारा सभी राज्यों तथा अन्य इकाइयों को सम्प्रेषित किया जाएगा, जो इस अभिसमय अथवा बोर्ड के पक्षकार हैं, अथवा बनने के हकदार हैं। ऐसा निर्णय सूचना मिलने की तारीख के एक सौ अस्सीवें दिन के पश्चात प्रत्येक पक्ष के लिए पूर्णतः प्रभावी हो जाएगा।

7. (क) इस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोग द्वारा लिए गए निर्णय, इन निर्णयों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात एक सौ अस्सी दिन के भीतर किसी पक्ष द्वारा दाखिल अनुरोध पर परिषद द्वारा पुनरीक्षण के अधीन होंगे। पुनरीक्षण के लिए अनुरोध सभी संगत सूचनाओं के साथ जिनपर पुनरीक्षण के लिए अनुरोध आधारित होगा, महासचिव को भेजा जाएगा।

(ख) महासचिव पुनरीक्षण के लिए अनुरोध और संगत सूचना की प्रतियों को आयोग, बोर्ड और सभी पक्षकारों को भेजकर नब्बे दिनों के भीतर उनको टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा। सभी प्राप्त टिप्पणियों को विचारार्थ परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) परिषद, आयोग के निर्णय की पुष्टि कर सकता है अथवा उसे बदल सकता है। परिषद के निर्णय की अधिसूचना सभी राज्यों और अन्य इकाइयों, जो इस अभिसमय, आयोग और बोर्ड के पक्षकार हैं, अथवा जो इसके पक्षकार बनने के हकदार हैं, को भेजी जाएगी।

8. (क) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में निहित प्रावधानों और 1961 के अभिसमय यथासंशोधित 1961 के अभिसमय और 1971 के अभिसमय के प्रति सामान्यतया पूर्वाग्रह के बिना, पक्षकार तालिका-1 और तालिका-11 में दिए गए पदार्थ जो उनके क्षेत्रों के भीतर तैयार किए जाते हैं, के निर्माण और वितरण को मॉनीटर करने के लिए जो उपयुक्त समझे, उपाय कर सकते हैं।

(ख) इसके पक्षकार इसके लिए;

(i) ऐसे पदार्थों के निर्माण और वितरण में संलग्न सभी व्यक्तियों और ऐसे सभी उद्यमों को नियंत्रित करेंगे;

(ii) संस्थापन और परिसर जहां ऐसे निर्माण अथवा वितरण हो सकते हैं को अनुज्ञप्ति के अंतर्गत नियंत्रित करना;

(iii) उपरोक्त संचालन के लिए अनुज्ञप्ति धारी के लिए परमिट लेने की अपेक्षा;

(iv) व्यापार और मौजूदा विपणन परिस्थितियों के सामान्य संचालन के लिए अपेक्षित अधिकतम मात्रा को निर्माताओं तथा वितरकों के अधिकार में ऐसे पदार्थों के एकत्रित होने को रोकना;

9. तालिका-1 और तालिका-11 में पदार्थों के मामले में प्रत्येक पक्ष निम्नलिखित उपाय करेंगे;

(क) संदिग्ध सौदों की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए तालिका-1 और तालिका-11 में पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मॉनीटर करने की प्रणाली को स्थापित करना और उसे कायम करना। ऐसी मॉनीटरिंग

746 GI/11-6

प्रणाली निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों होलसेलरों तथा रिटेलरों के साथ निकट सहयोग से लागू होगी जो सदिग्ध क्रयादेशों तथा सौदों के विषय में सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करेंगे।

(ख) औषध द्रव्यों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण में प्रयोग के लिए तालिका-1 अथवा तालिका-11 में से किसी पदार्थ के होने के पर्याप्त साक्ष्य हो तो उसे जब्त करवाने के लिए प्रदान करना।

(ग) यदि यह विश्वास हो जाने का कोई कारण हो कि तालिका-1 और तालिका-11 में दिया गया कोई पदार्थ आयात, निर्यात अथवा मार्गस्थ, अवैध द्रव्यों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण के लिए नियत है, जिसमें विशेष रूप से भुगतान के तरीके और किसी अन्य अनिवार्य तथ्य के विषय में ऐसी सूचना जो विश्वास को दृढ़ करती हो, के विषय में सम्बन्धित पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों अथवा सेवाओं को जितना शीघ्र सम्भव होगा, सूचित करें।

(घ) अपेक्षित है कि आयात और निर्यात पर उचित प्रकार से लेबल लगा हो और प्रलेखित हों। वाणिज्यिक दस्तावेज जैसे कि इनवॉयस, कार्गो, माल-सूची, सीमा-शुल्क, परिवहन तथा अन्य नौवहन दस्तावेजों में आयात अथवा निर्यात किए जा रहे पदार्थ का नाम जैसा कि तालिका-1 अथवा तालिका-11 में दिया गया है और आयात अथवा निर्यात किए जा रहे पदार्थ की मात्रा तथा निर्यातक, आयातक का नाम और पता, कब उपलब्ध होगा, प्रेषिती के नाम भी शामिल होंगे।

(ङ) यह सुनिश्चित करें कि इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (घ) में संदर्भित दस्तावेज कम से कम दो वर्ष की अवधि तक रखे जाए और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएं।

10. (क) पैराग्राफ 9 के प्रावधानों के अतिरिक्त, और इच्छुक पक्ष द्वारा महासचिव को किए गए अनुरोध पर, प्रत्येक पक्ष जिसके क्षेत्र से तालिका-1 के पदार्थ को निर्यात किया जाना है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से पूर्व, उसके सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आयातक देश के सक्षम प्राधिकारियों को निम्नलिखित सूचना दी जाए।

(i) निर्यातक और आयातक का नाम और पता, और कब उपलब्ध होंगे, प्रेषिती।

(ii) तालिका-1 में पदार्थ का नाम।

(iii) निर्यात किए जाने वाले पदार्थ की मात्रा।

(iv) प्रवेश का सम्भावित स्थान और प्रेषण की सम्भावित तारीख।

(v) दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमत कोई अन्य सूचना।

(ख) कोई पक्ष इस पैराग्राफ में दिए गए नियंत्रण के तरीकों से अधिक कठोर अथवा प्रचण्ड तरीके अपना सकता है, यदि उसके विचार से ऐसे तरीके वांछनीय अथवा अनिवार्य हैं।

11. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 9 और 10 के अनुसार जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को सूचना देता है, ऐसी सूचना भेजने वाला पक्ष यह अपेक्षा करेगा कि उसे प्राप्त करने वाला पक्ष किसी औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक, अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया को गोपनीय रखे।

12. प्रत्येक पक्ष हर वर्ष बोर्ड को, उसके द्वारा बताए तरीके और प्रक्रिया के अनुसार और उसके द्वारा उपलब्ध फार्म पर सूचना भेजेंगे ।

(क) तालिका-I और तालिका-II में दिए गए पदार्थ की कुल जल मात्रा और कब जानकारी मिली उसका स्रोत;

(ख) तालिका-I अथवा तालिका-II में शामिल न गया कोई पदार्थ जिसका, औषध द्रव्यों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण में प्रयोग किए जाने के बारे में मालूम हुआ है और जिसे पक्षकार द्वारा बोर्ड के ध्यान में लाने के लिए पर्याप्त रूप से विशिष्ट समझा गया है;

(ग) विपथन और अवैध निर्माण के तरीके;

13. बोर्ड इस अनुच्छेद के कार्यान्वयन पर आयोग को हर वर्ष रिपोर्ट देगा और आयोग तालिका-I और तालिका-II की पर्याप्तता और उपयुक्तता का आवधिक पुनरीक्षण करेगा ।

14. इस अनुच्छेद के प्रावधान भेषजीय संपाकों पर लागू नहीं होंगे, न ही तालिका-I और तालिका-II में निहित पदार्थों के अन्य संपाकों पर जो इस तरह से मिश्रित किए जाते हैं कि ऐसे पदार्थ तत्काल प्रयोज्य तरीकों द्वारा आसानी से प्रयोग अथवा पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते ।

अनुच्छेद - तेरह सामग्री और उपस्कर

दोनों पक्षकार औषध द्रव्यों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध उत्पादन अथवा निर्माण के लिए सामग्री और उपस्कर के व्यापार और विपथन को रोकने के लिए जो उपाय उचित समझेंगे करेंगे और इसके लिए सहयोग देंगे ।

अनुच्छेद - चौदह अवैध औषधों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के लिए औषध पौधों की अवैध उपज का उन्मूलन और अवैध मांग को समाप्त करना

1. पक्षकारों द्वारा इस अभिसमय के अनुपालन में किया गया कोई उपाय 1961 के अभिसमय, यथासंशोधित 1961 के अभिसमय और 1971 के अभिसमय के प्रावधानों के अंतर्गत औषध द्रव्यों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के लिए अवैध मांग को समाप्त करने और स्वापक तथा मनः प्रभावी पदार्थ निहित पौधों की अवैध खेती के उन्मूलन के प्रयोज्य उपबन्धों से कम कटोर नहीं होंगे ।

2. प्रत्येक पक्ष अपने क्षेत्र में अपीम, कोक और भांग के पौधों की अवैध खेती जैसे स्वापक अथवा मनः प्रभावी पदार्थ निहित अवैध खेती को रोकने और पौधों के उन्मूलन के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे । किए गए उपायों से मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान होगा और परम्परागत विधि सम्मत प्रयोगों और इसके साथ ही पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा ।

3. (क) उन्मूलन के प्रयासों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पक्षकारों द्वारा सहयोग किया जाए। इस सहयोग में अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत ग्राम्य विकास के लिए ऐसी सहायता जो अवैध कृषि का आर्थिक रूप से साध्य विकल्प बन सके, जब भी उपयुक्त हो, देना शामिल है।

ऐसे ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पहले बाजारों तक पहुँच, संसाधनों की उपलब्धता और प्रचलित सामाजिक-आर्थिक स्थितियों जैसे घटकों को भी ध्यान में रखा जाए। पक्षकार, सहयोग के किसी अन्य उपयुक्त उपाय पर भी सहमत हो सकते हैं।

(ख) पक्षकार, उन्मूलन से सम्बन्धित वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान और उन्मूलन संबंधी शोध किए जाने को भी सुकर बनाएंगे।

(ग) जहाँ भी सीमान्त क्षेत्र सहवर्ती हों वहाँ पक्षकार, इन सीमान्त क्षेत्रों के साथ लगे अपने-अपने क्षेत्रों में उन्मूलन कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे।

4. मानव वेदना को घटाने और अवैध व्यापार के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का उन्मूलन करने की दृष्टि से पक्षकार, स्वापक औषध एवं मनोत्तेजक पदार्थों की अवैध मांग को घटाने अथवा समाप्त करने के प्रति लक्षित समुचित उपाय करेंगे। ये उपाय, अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, और अन्य सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की संस्तुतियों पर, तथा निवारण, उपचार एवं पुनर्वास के क्षेत्र में निजी प्रयासों, सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से यथा-सम्बद्ध और 1987 में नशीली दवाइयों एवं अवैध व्यापार के बारे में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा अंगीकृत व्यापक बहु आयामी रूपरेखा पर आधारित हो सकते हैं। स्वापक औषधों एवं मनोत्तेजक पदार्थों की अवैध मांग को समाप्त करने अथवा घटाने के प्रति लक्षित द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते या व्यवस्थाएं भी पक्षकारों द्वारा की जा सकती हैं।

5. पकड़ी गई अथवा जब्त की गई स्वापक औषधों, मनोत्तेजक पदार्थों तथा तालिका-I एवं तालिका-II में वर्णित पदार्थों को शीघ्र नष्ट किए जाने अथवा कानूनी ढंग से निस्तारण किए जाने के लिए और ऐसे पदार्थों की विधिवत् प्रमाणित आवश्यक मात्रा को प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने के संबंध में आवश्यक उपाय भी पक्षकारों द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 15

वाणिज्यिक वाहक

1. पक्षकार यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएंगे कि वाणिज्यिक वाहकों द्वारा संचालित परिवहन के साधनों का प्रयोग अनुच्छेद-3, पैराग्राफ-1 के अनुरूप अपराध घोषित कृत्यों में न किया जाए; ऐसे उपायों में वाणिज्यिक वाहकों के साथ विशेष व्यवस्थाएं किया जाना शामिल है।

2. प्रत्येक पक्षकार, वाणिज्यिक वाहकों को यह आदेश देगा कि उनके द्वारा संचालित परिवहन के साधनों का प्रयोग अनुच्छेद-3, पैराग्राफ-1 के अनुरूप अपराध घोषित कृत्यों में किए जाने से रोकने के लिए वे उचित सावधानियां बरतें। ऐसी सावधानियों में निम्नलिखित उपाय शामिल हो सकते हैं -

(क) यदि किसी वाणिज्यिक वाहक के व्यापार का प्रधान स्थल, पक्षकार के राज्य क्षेत्र के अन्दर है तो:

- (i) सन्देहास्पद परेषणों अथवा व्यक्तियों की पहचान के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना;
- (ii) कार्मिकों की निष्ठा को बढ़ावा देना;
- (ख) यदि कोई वाणिज्यिक वाहक, पक्षकार के राज्य क्षेत्र में कार्य संचालन कर रहा हो तो -
 - (i) कार्गो का विवरण, जहां भी संभव हो, अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना;
 - (ii) कंटेनरों पर रद्दो-बदल रोधी, वैयक्तिक रूप से सत्यापित की जा सकने वाली सील का प्रयोग करना;
 - (iii) अनुच्छेद-3, पैराग्राफ-1 के अनुरूप अपराध घोषित कृत्य से संभावित रूप से जुड़ी सभी सन्देहास्पद परिस्थितियों की सूचना पहला अवसर मिलते ही सक्षम प्राधिकारियों को देना ।

3. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वाणिज्यिक वाहक और प्रवेश एवं निकास स्थलों पर तथा अन्य सीमा शुल्क नियंत्रण क्षेत्रों में तैनात सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहयोग करें ताकि परिवहन के साधनों और कार्गो तक अनधिकृत पहुँच को रोका जा सके तथा समुचित सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकें ।

अनुच्छेद - 16

वाणिज्यिक दस्तावेज और निर्यात सामग्री पर लेबल लगाना

1. प्रत्येक पक्षकार यह आदेश देगा कि स्वापक औषधों एवं मनोत्तेजक पदार्थों के विधिसम्मत निर्यात को समुचित रूप से प्रलेखबद्ध किया जाए । 1961 के अभिसमय के अनुच्छेद-31, 1961 के यथासंशोधित अभिसमय के अनुच्छेद-31 और 1971 के अभिसमय के अनुच्छेद-12 के अधीन प्रलेखन की अपेक्षाओं के अलावा बीजकों, कार्गो विवरणों, सीमाशुल्क, परिवहन एवं अन्य नौवहन दस्तावेजों जैसे वाणिज्यिक दस्तावेजों में निर्यात किए जा रहे स्वापक औषध एवं मनोत्तेजक पदार्थों के नाम, जैसा कि 1961 के अभिसमय, 1961 के यथासंशोधित अभिसमय और 1971 के अभिसमय की संबंधित अनुसूचियों में निर्धारित है; निर्यात की मात्रा, निर्यातक का नाम एवं पता, आयातक का नाम और जब उपलब्ध हो तो, परेषिती का नाम शामिल होगा ।

2. प्रत्येक पक्षकार यह आदेश देगा कि निर्यात किए जा रहे स्वापक औषध एवं मनोत्तेजक पदार्थों पर गलत लेबल न लगाया जाए ।

अनुच्छेद - 17

समुद्र मार्ग से अवैध व्यापार

1. पक्षकार, समुद्र से होकर होने वाले अवैध व्यापार को रोकने के लिए अधिकतम सम्भव सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र कानून के अनुरूप करेंगे ।

2. वह पक्षकार जिसके पास यह सन्देह करने के पर्याप्त आधार हैं कि जिस जहाज पर उसका झण्डा फहरा रहा है या फिर जिस पर कोई कोई झण्डा या पंजीयन चिन्ह नहीं दिख रहा है, वह अवैध व्यापार में लिप्त है तो वह अपने ध्वज के उस उद्देश्य हेतु प्रयोग के रोकने के लिए अन्य पक्षकारों की सहायता मांग सकता है । इस प्रकार अनुरोध प्राप्त पक्षकार, अपने पास उपलब्ध साधनों की सीमा में उक्त प्रकार की सहायता देगा ।

746 GI/11-7

3. वह पक्षकार जिसके पास यह सन्देह करने के पर्याप्त आधार हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौकागमन की स्वतन्त्रता प्राप्त और किसी दूसरे पक्षकार का ध्वज लगाए हुए अथवा पंजीयन चिन्ह प्रदर्शित कर रहा जहाज किसी अवैध व्यापार में संलिप्त है तो वह ध्वज वाले राज्य को अधिसूचित करेगा, पंजीयन की पुष्टि का अनुरोध करेगा और यदि पुष्टि हो जाती है तो ध्वज वाले राज्य से अनुरोध करेगा कि उस जहाज के संबंध में समुचित कदम उठाने का प्राधिकार उसे दिया जाए ।
 4. पैरा-3 के अनुरूप अथवा उनके बीच हुई किसी संधि के अनुरूप अथवा उन पक्षकारों के बीच अन्यथा हुई किसी व्यवस्था या समझौते के अनुरूप, ध्वज वाला राज्य, अनुरोधकर्ता राज्य को अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकार दे सकता है कि वह -
 - (क) जहाज पर चढ़ सकता है;
 - (ख) जहाज की तलाशी ले सकता है;
 - (ग) यदि अवैध व्यापार में संलिप्तता का साक्ष्य पाया जाता है तो उस जहाज के, व्यक्तियों के और उस पर लदे कार्गो के संबंध में समुचित कार्रवाई कर सकता है ।
 5. जहां इस अनुच्छेद के अनुसरण में कार्रवाई की जाती है वहां सम्बन्धित पक्ष इस बात की जरूरत पर उचित ध्यान देंगे कि समुद्र में जीवों की सुरक्षा को, जहाज एवं कार्गो की संरक्षा को खतरा न पहुँचे और न ही ध्वज से जुड़े राज्य के अथवा किसी अन्य हितधारक राज्य के वाणिज्यिक एवं विधायी हितों के प्रति पूर्वाग्रह दिखे ।
 6. इस अनुच्छेद के पैरा-1 में अपने दायित्वों के अनुरूप ध्वज राज्य अपना प्राधिकार अपने और अनुरोधकर्ता राज्य के बीच परस्पर सहमत शर्तों के अधीन कर सकता है; इसमें जिम्मेदारी से जुड़ी शर्तें भी शामिल हैं ।
 7. इस अनुच्छेद के पैरा 3 एवं 4 के उद्देश्यों हेतु कोई भी पक्षकार, किसी अन्य पक्षकार से प्राप्त अनुरोध पर और पैराग्राफ -3 के अनुसरण में प्राधिकार देने के लिए किए गए अनुरोध पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए यह निर्धारित करेगा कि उसका ध्वज फहराने वाला जहाज, ऐसा करने के लिए अधिकृत है या नहीं ।
- इस अभिसमय का पक्षकार बनने के समय प्रत्येक पक्ष ऐसे अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए किसी प्राधिकारी अथवा आवश्यक होने पर प्राधिकारियों को नाम-निर्दिष्ट करेगा । ऐसे नाम-निर्दिष्ट किए जाने संबंधी अधिसूचना, नाम-निर्दिष्ट होने के एक महीने के अन्दर, महासचिव के माध्यम से अन्य सभी पक्षों को दी जाएगी ।
8. वह पक्षकार जिसने इस अनुच्छेद के अनुसार कोई कार्रवाई की है, तुरन्त ही सम्बन्धित ध्वज राज्य को, उस कार्रवाई के परिणाम की सूचना देगा ।
 9. इस अनुच्छेद के प्रावधानों को पूरा करने, अथवा इनकी प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए पक्षकार, द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय समझौते या व्यवस्थाएं करने पर विचार करेंगे ।

10. इस अनुच्छेद के पैरा-4 के अनुसरण में कार्रवाई केवल युद्धक जहाजों अथवा सैन्य वायुयानों अथवा स्पष्ट रूप से चिह्नांकित और सरकारी सेवा पर होने की पहचान कराने योग्य एवं इस आशय के लिए प्राधिकृत अन्य जहाजों अथवा वायुयानों द्वारा ही की जाएगी।

11. इस अनुच्छेद के अनुरूप की गई कोई कार्रवाई करते समय इस आवश्यकता का उचित ध्यान रखा जाएगा कि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र कानून के अनुसार तटवर्ती राज्यों के क्षेत्राधिकार के निर्वहन में उनके अधिकारों एवं दायित्वों में कोई हस्तक्षेप अथवा प्रभाव न पड़े।

अनुच्छेद - 18

मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा मुक्त समुद्रपत्तन

1. मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा मुक्त समुद्रपत्तनों में स्थापक औषधों एवं मनोत्तेजक पदार्थों के तथा तालिका-I एवं तालिका-II में शामिल पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए पक्षकार ऐसे कड़े उपाय लागू करेंगे जो कि उनके राज्य क्षेत्रों के अन्य हिस्सों में लागू उपायों से कम कड़े न हों।

2. पक्षकार निम्नलिखित के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे -

(क) मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा मुक्त समुद्रपत्तनों में सामान एवं व्यक्तियों की आवाजाही का अनुवीक्षण करेंगे और इस दिशा में सक्षम प्राधिकारियों को यह अधिकार देंगे कि वे मनोरंजनार्थ जहाजों एवं मछली पकड़ने वाली नौकाओं सहित कार्गो और आने वाले एवं जाने वाले जहाजों की तलाशी के साथ-साथ वायुयान एवं वाहनों की तलाशी ले सकें और जहां उपयुक्त हो वहां चालक दल के सदस्यों, यात्रियों और उनके सामानों की भी तलाशी ले सकें।

(ख) मुक्त व्यापार क्षेत्रों एवं मुक्त समुद्रपत्तनों से होकर आने या जाने वाले ऐसे परेषणों का जिनमें स्थापक औषध तथा मनोत्तेजक पदार्थ तथा तालिका-I एवं तालिका-II में शामिल पदार्थ होने का संदेह हो, पता लगाने की प्रणाली स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे।

(ग) मुक्त व्यापार क्षेत्रों एवं मुक्त समुद्रपत्तनों में स्थित सीमा नियंत्रण स्थलों एवं हवाई अड्डों पर तथा बन्दरगाह एवं जेटी क्षेत्रों में निगरानी प्रणालियां स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 19

डाक व्यवस्था का प्रयोग

1. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अभिसमयों के अधीन अपने दायित्वों की पुष्टि स्वरूप और अपनी घरेलू कानूनी प्रणालियों के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुरूप पक्षकार डाक व्यवस्था का प्रयोग अवैध व्यापार में किए जाने से रोकने के लिए उपाय करेंगे और इस दिशा में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैरा-1 में उल्लिखित उपायों में निम्नलिखित उपाय खास तौर से शामिल होंगे -

(क) डाक व्यवस्था का प्रयोग अवैध व्यापार के लिए किए जाने से रोकने और इसके निवारण के लिए सम्बन्धित कार्रवाई करना;

(ख) स्वापक औषधों एवं मनोत्तेजक पदार्थों तथा तालिका-I एवं तालिका-II में शामिल पदार्थों का डाक द्वारा अवैध परेषण किए जाने का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई अन्वेषणात्मक एवं नियंत्रण तकनीकों को लागू करना और उनका रख-रखाव प्राधिकृत विधि प्रवर्तन कार्मिकों द्वारा किया जाना;

(ग) ऐसे उपाय करना जिनसे कि न्यायिक कार्यवाही के लिए अपेक्षित साक्ष्य जुटाने के लिए समुचित साधनों का प्रयोग सुकर हो सके ।

अनुच्छेद - 20

पक्षकारों द्वारा सौंपी जाने वाली जानकारी

1. पक्षकार अपने राज्यक्षेत्र में इस अभिसमय के कार्यक्रम के बारे में, महासचिव के माध्यम से जानकारी सौंपेंगे और खास तौर से -

(क) अभिसमय को लागू करने की दृष्टि से प्रवर्तित किए गए कानूनों एवं विनियमों का पाठ सौंपेंगे;

(ख) अपने क्षेत्राधिकार में अवैध व्यापार के ऐसे मामलों का विवरण जिन्हें वे इस लिए महत्वपूर्ण समझते हों कि उसके माध्यम से नई प्रवृत्तियों का पता चलता हो, शामिल मात्रा, वह स्रोत जहां से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं अथवा इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा अपनाए जा रहे तौर-तरीके की सूचना देंगे ।

2. पक्षकार उक्त सूचना इस तरीके से और उस तिथि तक प्रस्तुत करेंगे जैसे कि आयोग ने अनुरोध किया हो ।

अनुच्छेद - 21

आयोग के प्रकार्य

आयोग को इस अभिसमय के उद्देश्यों से सम्बन्धित सभी मामलों पर और खास तौर से निम्नलिखित पर विचार करने का अधिकार है :

(क) अनुच्छेद-20 के अनुरूप पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर आयोग, इस अभिसमय के प्रचालन की समीक्षा करेगा;

(ख) पक्षकारों से प्राप्त सूचना की जांच के आधार पर आयोग अपने सुझाव एवं सामान्य संस्तुतियां भी दे सकता है;

(ग) आयोग, ऐसे किन्हीं मामलों के बारे में बोर्ड का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो कि बोर्ड के प्रकार्यों से जुड़े हों;

(घ) अनुच्छेद-22 के पैरा-1 (ख) के अलीन बोर्ड द्वारा आयोग को भेजे गए किसी मामले पर आयोग ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह उचित समझे;

(ड) अनुच्छेद-12 में निर्धारित पद्धतियों के अनुरूप आयोग तालिका-I एवं तालिका-II में संशोधन कर सकता है;

(च) आयोग, इस अभिसमय के अधीन स्वयं द्वारा अंगीकृत निर्णयों और संस्तुतियों पर गैर-पक्षकारों का ध्यान इस दृष्टि से आकर्षित कर सकता है कि वे उनके अनुरूप कार्रवाई करने पर विचार करें।

अनुच्छेद - 22

बोर्ड के प्रकार्य

1. अनुच्छेद-21 के अधीन आयोग के प्रकार्यों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना और 1961 के अभिसमय, 1961 के यथा संशोधित अभिसमय और 1971 के अभिसमय के अधीन बोर्ड एवं आयोग के प्रकार्यों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना -

(क) यदि अपने पास, महासचिव के पास अथवा आयोग के पास उपलब्ध सूचना की जांच अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के घटकों द्वारा भेजी गई सूचना की जांच के आधार पर बोर्ड के पास यह विश्वास करने की वजह मौजूद है कि बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों में अभिसमय के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो बोर्ड, कोई संगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किसी पक्षकार या पक्षकारों को आमंत्रित कर सकता है;

(ख) अनुच्छेद 12, 13, एवं 16 के संबंध में :

(i) इस अनुच्छेद के उप पैरा (क) के अधीन कार्रवाई करने के बाद बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो संबंधित पक्ष से ऐसे उपचारात्मक उपाय करने का आह्वान कर सकता है जो कि अनुच्छेद 12, 13, एवं 16 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उन परिस्थितियों में जरूरी समझे जाएं;

(ii) नीचे दिए गए उप पैरा (iii) के अधीन कार्रवाई करने से पहले बोर्ड, पिछले उप पैराग्राफों के अधीन संबंधित पक्ष के साथ किए गए अपने पत्र व्यवहार को गोपनीय रखेगा।

(iii) यदि बोर्ड यह पाता है कि संबंधित पक्ष ने ऐसे कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए हैं जिनके लिए आह्वान उससे, इस उप-पैराग्राफ के अधीन किया गया था तो वह इस बारे में पक्षकारों का, परिषद का और आयोग का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इस उप पैराग्राफ के अधीन बोर्ड द्वारा प्रकाशित किसी रिपोर्ट में, संबंधित पक्षकार का मत भी दिया जाए, यदि वह ऐसा किए जाने का अनुरोध करे तो।

2. किसी पक्षकार को बोर्ड की ऐसी बैठक में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जिसमें कि इस अनुच्छेद के अधीन उसके प्रत्यक्ष हित वाले किसी प्रश्न पर विचार किया जाना हो।

3. यदि किसी स्थिति में बोर्ड द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन अंगीकृत निर्णय सर्वसम्मत नहीं है तो अल्पमत सदस्यों के विचारों का भी उल्लेख किया जाएगा।

4. इस अनुच्छेद के अधीन बोर्ड के निर्णय, बोर्ड की कुल संख्या के दो-तिहाई बहुमत से लिए जाएंगे।

5. इस अनुच्छेद के उप पैराग्राफ 1 (क) के अनुसरण में अपने प्रकार्यों को पूरा करते हुए बोर्ड, अपने पास पहुँची समस्त जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

746 GI/11-8

6. इस अनुच्छेद के तहत बोर्ड का उत्तरदायित्व इस अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों के बीच संपन्न संधियों या करारों के क्रियान्वयन पर लागू नहीं होंगे।

7. इस अनुच्छेद के प्रावधान अनुच्छेद 32 के तहत आने वाले पक्षकारों के बीच विवादों के लिए लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद तेईस बोर्ड की रिपोर्टें

1. बोर्ड अपने कार्य पर उसके पास उपलब्ध सूचना का एक विप्लेषण समाविष्ट करते हुए तथा, उपयुक्त मामलों में, स्पष्टीकरणों का लेखा जोखा, यदि कोई, पक्षकारों द्वारा दिया गया या अपेक्षित है, उन किन्हीं टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ जिन्हें बोर्ड देना चाहता है, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। बोर्ड इस प्रकार की अतिरिक्त रिपोर्टें तैयार कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझता है। रिपोर्टें कमीशन के जरिए परिषद को प्रस्तुत की जाएंगी जो इस प्रकार की टिप्पणियां दे सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझता है।

2. बोर्ड की रिपोर्टें पक्षकारों को संप्रेषित होंगी और तत्पश्चात महासचिव द्वारा प्रकाशित होंगी। पक्षकार अपने अपने अप्रतिबंधित वितरण की अनुमति देंगे।

अनुच्छेद चौबीस इस अभिसमय द्वारा अपेक्षित उपायों से अधिक कठोर उपायों का उपयोग

कोई पक्षकार इस अभिसमय द्वारा प्रदत्त उन उपायों से अधिक कठोर या सख्त उपाय अपना सकता है, यदि उसकी राय में, ऐसे उपाय अवैध व्यापार को रोकने या दमन के लिए वांछनीय या आवश्यक हैं।

अनुच्छेद पच्चीस पूर्ववर्ती संधि अधिकारों और बाध्यताओं का अनादर नहीं

इस अभिसमय के प्रावधान 1961 अभिसमय के तहत इस अभिसमय के पक्षकारों द्वारा उपयोग किए गए किन्हीं अधिकारों अथवा धारण की गई बाध्यताओं का अनादर नहीं करेंगे, 1961 अभिसमय यथा संशोधित और 1971 अभिसमय।

अनुच्छेद छत्वीस हस्ताक्षर

यह अभिसमय वियेना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में 20 दिसंबर 1998 से 28 फरवरी 1989 तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा तथा इसके पश्चात न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 20 दिसंबर 1989 तक हस्ताक्षर के लिए :

(क) सभी राज्यों ;

(ख) नामीबिया, नामीबिया संबंध संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा प्रतिनिधित्व ।

(ग) क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों जिनकी वार्ता, निष्कर्ष और इस अभिसमय के अंतर्गत मामलों में अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रवर्तन संबंध में पक्षकारों के लिए इस अभिसमय के अंतर्गत विषय, इन संगठनों के लिए प्रवर्तनीय होते हुए अपनी अपनी सीमाओं के भीतर राज्यों या राष्ट्रीय सेवाओं सक्षमता है ।

अनुच्छेद सत्ताईस

अनुसमर्थन स्वीकृति, अनुमोदन या औपचारिक पुष्टि का कृत्य

1. यह अभिसमय अनुच्छेद 26 के उप पैरा ग में उल्लिखित राज्यों और नामीबिया, नामीबिया संबंध संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा प्रतिनिधित्व तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों द्वारा औपचारिक पुष्टि के कृत्यों के लिए अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के अध्वधीन है । अनुसमर्थन स्वीकृति या अनुमोदन के दस्तावेज और वे दस्तावेज जो औपचारिक पुष्टि के कृत्यों से संबंधित है ; महासचिव के पास जमा होंगे ।

2. औपचारिक पुष्टि के अपने अपने दस्तावेजों में, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन इस अभिसमय द्वारा प्रशासित मामलों के संबंध में अपनी अपनी सक्षमता की सीमा घोषित करेंगे । ये संगठन इस अभिसमय द्वारा प्रशासित मामलों के संबंध में अपनी अपनी सक्षमता की सीमा में किसी संशोधन को भी महासचिव को सूचित करेंगे ।

अनुच्छेद अट्ठाईस

स्वीकृति

1. यह अभिसमय किसी राज्य, नामीबिया, नामीबिया, संबंधी संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा प्रतिनिधित्व, और अनुच्छेद 26, उप पैरा ग में उल्लिखित क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों की स्वीकृति के लिए खुला रहेगा । स्वीकृति महासचिव के पास स्वीकृति के एक दस्तावेज के जमा करने पर प्रभावी होगी ।

2. स्वीकृति के अपने दस्तावेजों में, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन इस अभिसमय द्वारा प्रशासित मामलों के संबंध में अपनी अपनी सक्षमता की सीमा को घोषित करेंगे । ये संगठन इस अभिसमय द्वारा प्रशासित मामलों के संबंध में अपनी अपनी सीमा में किसी संशोधन के बारे में महासचिव को भी सूचित करेंगे ।

अनुच्छेद उनतीस

प्रवर्तन

1. यह अभिसमय अनुसमर्थन, स्वीकृति अनुमोदन या राज्यों या नामीबिया संबंधी परिषद द्वारा प्रतिनिधित्व द्वारा अंगीकरण के बीसवें दस्तावेज के महासचिव के जमा करने की विधि के पश्चात् नब्बेवें दिन को लागू होगा ।

2. प्रत्येक राज्य या नामीबिया, नामीबिया संबंधी परिषद द्वारा प्रतिनिधित्व, के लिए इस अभिसमय को अनुसमर्थित करते हुए, स्वीकार करते हुए, अनुमोदित अथवा अंगीकार करते हुए अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अंगीकरण के बीसवें दस्तावेज के जमा करने के पश्चात, यह अभिसमय इसके अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अंगीकरणों के अपने दस्तावेज के जमा करने की तिथि के पश्चात नब्बे वें दिन को प्रभावी होगा ।

3. अनुच्छेद 26, उप पैरा ग में उल्लिखित प्रत्येक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन औपचारिक पुष्टिकरण के कृत्य या अंगीकरण के एक दस्तावेज से संबंधित किसी दस्तावेज को जमा करते हुए यह अभिसमय ऐसे जमा करने के पश्चात नब्बेवें दिन को या इस अनुच्छेद के पैरा के अनुसरण में अभिसमय प्रभावी होता है, की तिथि को, प्रभावी होगा, जो भी बाद में हो ।

अनुच्छेद तीस समापन

1. इस अभिकरण को कोई पक्ष किसी समय महासचिव को संबोधित एक लिखित अधिसूचना द्वारा समाप्त कर सकता है ।
2. ऐसा समापन संबंधित पक्ष के लिए महासचिव द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि के एक वर्ष पश्चात प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद इकतीस संशोधन

1. कोई पक्ष इस अभिसमय में कोई संशोधन प्रस्तावित कर सकता है । ऐसे किसी संशोधन का पाठ और उसके कारण उस पक्ष द्वारा महासचिव के लिए संप्रेषित किए जाएंगे; जो उन्हें अन्य पक्षों को संप्रेषित करेगा और उनसे कहेगा क्या वे प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हैं। यदि इस प्रकार परिचालित एक प्रस्तावित संशोधन इसके परिचालित होने के पश्चात चौबीस माह के भीतर किसी पक्ष द्वारा खारिज नहीं किया गया है, उसे स्वीकृत हुआ माना जाएगा और उस पक्ष के उस संशोधन द्वारा बाध्य होने की अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए महासचिव के पास एक दस्तावेज जमा हो जाने किसी पक्ष के संबंध में नब्बे दिन पश्चात प्रभावी होगा ।
2. यदि कोई प्रस्तावित संशोधन किसी पक्ष द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो महासचिव पक्षों के साथ परामर्श करेगा और यदि एक बहुमत ऐसा अनुरोध करता है, तो वह मामले के पक्षों द्वारा की गई किन्हीं टिप्पणियों के साथ, परिषद के समक्ष लाएंगे, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 62, पैराग्राफ 4 के अनुसार एक सम्मेलन आहूत करने का फैसला करेगी । ऐसे किसी सम्मेलन के फलस्वरूप किसी संशोधनको संशोधन के एक प्रोटोकोल में सम्मिलित किया जाएगा । ऐसे किसी प्रोटोकोल द्वारा बाध्य होने की सहमति को महासचिव के लिए स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना अपेक्षित होगा ।

अनुच्छेद वत्तीस विवादों का निपटारा

1. यदि इस अभिसमय की व्याख्या या प्रवर्तन के संबंध में दो या अधिक पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो पक्षकारों द्वारा विवाद के निपटारे को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ वार्ता, पूछताछ, मध्यस्थता, सुलह, विवाचन, क्षेत्रीय निकाओं न्यायिक प्रक्रिया अथवा अपनी पसंदी के अन्य शांतिपूर्ण साधनों के सहारे द्वारा परामर्श करेंगे।
2. ऐसा कोई विवाद जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्धारित रीति से नहीं सुलझाया जा सकता है, निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, विवाद के राज्य पक्षकारों में से किसी एक के अनुरोध पर, सौंपा जाएगा।
3. यदि अनुच्छेद 26, उप पैरा ग में उल्लिखित कोई क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन किसी विवाद का एक पक्ष है जिसका इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्धारित रीति से समाधान नहीं हो सकता है, वह संयुक्त राष्ट्र के किसी राज्य सदस्य के जरिए न्यायालय के विधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक सलाहकारी राय का अनुरोध करने के लिए परिषद से अनुरोध कर सकता है, वह राय निर्णायक के रूप में मानी जाएगी।
4. प्रत्येक राज्स, हस्ताक्षर के समय पर, या इस अभिसमय के अनसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन या इसके अंगीकरण, या प्रत्येक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन, हस्ताक्षर करने, औपचारिक पुष्टिकरण के एक कृत्य को जमा करने, या अंगीकरण के समय पर, घोषित कर सकता है कि वह इस अनुच्छेद के पैरा 2 और 3 द्वारा अपने आपको बाध्य नहीं करता है। अन्य पक्षकार ऐसा कोई घोषणा किए हुए किसी पक्षकार के संबंध में पैरा 2 और 3 के पैराग्राफों द्वारा बाध्य नहीं होंगे।
5. इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार एक घोषणा करते हुए कोई पक्ष महासचिव को अधिसूचना द्वारा घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है।

अनुच्छेद तैंतीस
प्रमाणिक पाठ

इस अभिसमय के अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

अनुच्छेद चौंतीस
जमाकर्ता

महासचिव इस अभिसमय का जमाकर्ता होंगे।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होते हुए, इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

746 GI/11-9

वियना में, एक मूल पाठ में, आज दिनांक ईस्वी सन् एक हजार नौ सौ अट्ठानवे के दिसम्बर माह के बीसवें दिन ।

अतः अब, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1962 का 34) की धारा 3 के उप धारा 4 प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश करती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान, अध्याय III के अलावा, उल्लिखित अभिसमय में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से कोशिया के लिए लागू होंगे ।

[फा. सं. टी-413/84/2010]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कान्सुलर)

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(CPV DIVISION)**

ORDER

New Delhi, the 25th February, 2011

G.S.R. 115(E).—Whereas the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Croatia are Parties to the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances., (hereinafter referred to as the convention) which came into force on 11th November, 1990 in accordance with Article 29 (1);

WHEREAS Article 3 of the Convention sets forth the offences created thereunder;

WHEREAS Article 6 of the Convention makes those offences extraditable;

WHEREAS in the absence of a bilateral extradition treaty the Convention provides a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in Article 3;

WHEREAS the Government of India and the Government of Croatia do not have any bilateral extradition treaty currently operative;

WHEREAS sub-section (4) of section 3 of the Indian Extradition Act 1962 confers power on the Central Government to treat any Convention to which India and a foreign State are Parties, as an extradition treaty made by India with that foreign State providing for extradition in respect of the offences specified in that Convention, by notified order; and

WHEREAS the text of the 1988 United Nations Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances provides as follows ;

**UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE**

as adopted by the Conference at its 6th plenary meeting, on 19 December 1988

THE PARTIES to this Convention.

DEEPLY CONCERNED by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society,

DEEPLY CONCERNED ALSO by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity,

RECOGNIZING the links between illicit traffic and other related organized criminal activities which undermine the legitimate economies and threaten the stability, security and sovereignty of States,

RECOGNIZING ALSO that illicit traffic is an international criminal activity, the suppression of which demands urgent attention and the highest priority,

AWARE that illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of government, legitimate commercial and financial business, and society at all its levels,

DETERMINED to deprive persons engaged in illicit traffic of the proceeds of their criminal activities and thereby eliminate their main incentive for so doing,

DESIRING to eliminate the root causes of the problem of abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, including the illicit demand for such drugs and substances and the enormous profits derived from illicit traffic,

CONSIDERING that measures are necessary to monitor certain substances, including precursors, chemicals and solvents, which are used in the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, the ready availability of which has led to an increase in the clandestine manufacture of such drugs and substances,

DETERMINED to improve international co-operation in the suppression of illicit traffic by sea,

RECOGNIZING that eradication of illicit traffic is a collective responsibility of all States and that, to that end, co-ordinated action within the framework of international co-operation is necessary,

ACKNOWLEDGING the competence of the United Nations in the field of control of narcotic drugs and psychotropic substances and desirous that the international organs concerned with such control should be within the framework of that Organization,

REAFFIRMING the guiding principles of existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic substances and the system of control which they embody,

RECOGNIZING the need to reinforce and supplement the measures provided in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and the 1971 Convention on Psychotropic Substances, in order to counter the magnitude and extent of illicit traffic and its grave consequences,

RECOGNIZING ALSO the importance of strengthening and enhancing effective legal means for international co-operation in criminal matters for suppressing the international criminal activities of illicit traffic,

DESIRING to conclude a comprehensive, effective and operative international convention that is directed specifically against illicit traffic and that considers the various aspects of the problem as a whole, in particular those aspects not envisaged in the existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic substances,

HEREBY AGREE as follows:

Article 1

Definitions

Except where otherwise expressly indicated or where the context otherwise requires, the following definitions shall apply throughout this Convention:

- (a) "Board" means the International Narcotics Control Board established by the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (b) "Cannabis plant" means any plant of the genus Cannabis;
- (c) "Coca bush" means the plant of any species of the genus Erythroxylon;
- (d) "Commercial carrier" means any person or any public, private or other entity engaged in transporting persons, goods or mails for remuneration, hire or any other benefit;
- (e) "Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social Council of the United Nations;
- (f) "Confiscation", which includes forfeiture where applicable, means the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;
- (g) "Controlled delivery" means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II annexed to this Convention, or substances substituted for them, to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1 of the Convention;
- (h) "1961 Convention" means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;

- (i) "1961 Convention as amended" means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (j) "1971 Convention" means the Convention on Psychotropic Substances, 1971;
- (k) "Council" means the Economic and Social Council of the United Nations;
- (l) "Freezing" or "seizure" means temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court a competent authority;
- (m) "Illicit traffic" means the offences set forth in article 3, paragraphs 1 and 2, of this Convention;
- (n) "Narcotic drug" means any of the substances, natural or synthetic, in Schedules I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (o) "Opium poppy" means the plant of the species *Papaver somniferum* L;
- (p) "Proceeds" means any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1;
- (q) "Property" means assets of every kind, whether corporal or in corporal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;
- (r) "Psychotropic substance" means any substance, natural or synthetic, or any natural material in Schedules I, II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances, 1971;
- (s) "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations;
- (t) "Table I" and "Table II" mean the correspondingly numbered lists of substances annexed to this Convention, as amended from time to time in accordance with article 12;
- (u) "Transit State" means a State through the territory of which illicit narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II are being moved, which is neither the place of origin nor the place of ultimate destination thereof.

746 GI/11-10

Article 2

Scope of the Convention

1. The purpose of this Convention is to promote co-operation among the Parties so that they may address more effectively the various aspects of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances having an international dimension. In carrying out their obligations under the Convention, the Parties shall take necessary measures, including legislative and administrative measures, in conformity with the fundamental provisions of their respective domestic legislative systems.
2. The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.
3. A Party shall not undertake in the territory of another Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other Party by its domestic law.

Article 3

Offences and sanctions

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally:
 - (a) (i) The production, manufacture, extraction, preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention;
 - (ii) The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as amended;
 - (iii) The possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in (i) above;
 - (iv) The manufacture, transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances;
 - (v) The organization, management or financing of any of the offences enumerated in (i), (ii), (iii) or (iv) above;
- (b) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this

paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions;

(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences;

(c) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system:

(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such offence or offences;

(ii) The possession of equipment or materials or substances listed in Table I and Table II, knowing that they are being or are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances;

(iii) Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences established in accordance with this article or to use narcotic drugs or psychotropic substances illicitly;

(iv) Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counseling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

2. Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system, each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the possession, purchase or cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances for personal consumption contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention.

3. Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

4. (a) Each Party shall make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions which take into account the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation.

(b) The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, for an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the offender shall undergo measures such as treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration.

(c) Notwithstanding the preceding subparagraphs, in appropriate cases of a minor nature, the Parties may provide, as alternatives to conviction or punishment, measures such as education, rehabilitation or social reintegration, as well as, when the offender is a drug abuser, treatment and aftercare.

(d) The Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment, or in addition to conviction or punishment of an offence established in accordance with paragraph 2 of this article, measures for the treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration of the offender.

5. The Parties shall ensure that their courts and other competent authorities having jurisdiction can take into account factual circumstances which make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article particularly serious, such as:

(a) The involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender belongs;

(b) The involvement of the offender in other international organized criminal activities;

(c) The involvement of the offender in other illegal activities facilitated by commission of the offence;

(d) The use of violence or arms by the offender;

(e) The fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with the office in question;

(f) The victimization or use of minors;

(g) The fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational institution or social service facility or in their immediate vicinity or in other places to which school children and students resort for educational, sports and social activities;

(h) Prior conviction particularly for similar offences, whether foreign domestic, to the extent permitted under the domestic law of a Party.

6. The Parties shall endeavor to ensure that any discretionary legal powers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.

7. The Parties shall ensure that their courts or other competent authorities bear in mind the serious nature of the offences enumerated in paragraph 1 of this article and the circumstances enumerated in paragraph 5 of this article when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.

8. Each Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with paragraph 1 of this article, and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.

9. Each Party shall take appropriate measures, consistent with its legal system, to ensure that a person charged with or convicted of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, who is found within its territory, is present at the necessary criminal proceedings.

10. For the purpose of co-operation among the Parties under this Convention, including, in particular, co-operation under articles 5, 6, 7 und 9, offences established in accordance with this article shall not be considered as fiscal offences or as political offences or regarded as politically motivated, without prejudice to the constitutional limitations and the fundamental domestic law of the Parties.

11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.

Article 4

Jurisdiction

1. Each Party:

(a) Shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when:

(i) The offence is committed in its territory;

(ii) The offence is committed on board a vessel flying its flag or an aircraft which is registered under its laws at the time the offence is committed;

(b) May take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when:

(i) The offence is committed by one of its nationals or by a person who has his habitual residence in its territory;

(ii) The offence is committed on board a vessel concerning which that Party has been authorized to take appropriate action pursuant to article 17, provided that such jurisdiction shall be exercised only on the basis of agreements or arrangements referred to in paragraphs 4 and 9 of that article;

(iii) The offence is one of those established in accordance with article 3, paragraph 1, subparagraph (c) (iv), and is committed outside its territory with a view to the

746 GI/11-11

commission, within its territory, of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each Party:

(a) Shall also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party on the ground:

- (i) That the offence has been committed in its territory or on board a vessel flying its flag or an aircraft which was registered under its law at the time the offence was committed; or
- (ii) That the offence has been committed by one of its nationals;

(b) May also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party.

3. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a Party in accordance with its domestic law.

Article 5

Confiscation

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to enable confiscation of:

(a) Proceeds derived from offences established in accordance with article 3, paragraph 1, or property the value of which corresponds to that of such proceeds;

(b) Narcotic drugs and psychotropic substances, materials and equipment or other instrumentalities used in or intended for use in any manner in offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each Party shall also adopt such measures as may be necessary to enable its competent authorities to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article, for the purpose of eventual confiscation.

3. In order to carry out the measures referred to in this article, each Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.

4. (a) Following a request made pursuant to this article by another party having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, the

Party in whose territory proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article are situated shall:

(i) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, give effect to it; or

(ii) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by the requesting Party in accordance with paragraph 1 of this article, in so far as it relates to proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 situated in the territory of the requested party.

(b) Following a request made pursuant to this article by another Party having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, the requested Party shall take measures to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting Party or, pursuant to a request under subparagraph (a) of this paragraph, by the requested Party.

(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party.

(d) The provisions of article 7, paragraphs 6 to 19 are applicable *mutatis mutandis*. In addition to the information specified in article 7, paragraph 10, requests made pursuant to this article shall contain the following:

(i) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (i) of this paragraph, a description of the property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law;

(ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (ii), a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested;

(iii) In the case of a request pertaining to subparagraph (b), a statement of the facts relied upon by the requesting Party and a description of the actions requested.

(e) Each Party shall furnish to the Secretary-General the text of any of its laws and regulations which give effect to this paragraph and the text of any subsequent changes to such laws and regulations.

(f) If a Party elects to make the taking of the measures referred to in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph conditional on the existence of a relevant treaty, that Party shall consider this Convention as the necessary and sufficient treaty basis.

- (g) The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to this article.
5. (a) Proceeds or property confiscated by a Party pursuant to paragraph 1 or paragraph 4 of this article shall be disposed of by that Party according to its domestic law and administrative procedures.
- (b) When acting on the request of another Party in accordance with this article, a Party may give special consideration to concluding agreements on:
- (i) Contributing the value of such proceeds and property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, or a substantial part thereof, to intergovernmental bodies specializing in the fight against illicit traffic in and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances;
- (ii) Sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds or property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, in accordance with its domestic law, administrative procedures or bilateral or multilateral agreements entered into for this purpose.
6. (a) If proceeds have been transformed or converted into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.
- (b) If proceeds have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.
- (c) Income or other benefits derived from:
- (i) Proceeds;
- (ii) Property into which proceeds have been transformed or converted; or
- (iii) Property with which proceeds have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds.
7. Each Party may consider ensuring that the onus of proof be reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
8. The provisions of this article shall not be construed as prejudicing the rights of bona fide third parties.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provision of the domestic law of a Party.

Article 6

Extradition

1. This article shall apply to the offences established by the Parties in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offence in every extradition treaty to be concluded between them.

3. If a Party makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies. The Parties which require detailed legislation in order to use this Convention as a legal basis for extradition shall consider enacting such legislation as may be necessary.

4. The Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.

5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds upon which the requested Party may refuse extradition.

6. In considering requests received pursuant to this article, the requested State may refuse to comply with such requests where there are substantial grounds leading its judicial or other competent authorities to believe that compliance would facilitate the prosecution or punishment of any person on account of his race, religion, nationality or political opinions, or would cause prejudice for any of those reasons to any person affected by the request.

7. The Parties shall endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.

8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent, and at the request of the requesting Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition proceedings.

746 GI/11-12

9. Without prejudice to the exercise of any criminal jurisdiction established in accordance with its domestic law, a Party in whose territory an alleged offender is found shall:

(a) If it does not extradite him in respect of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, on the grounds set forth in article 4, paragraph 2, subparagraph (a), submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless otherwise agreed with the requesting Party;

(b) If it does not extradite him in respect of such an offence and has established its jurisdiction in relation to that offence in accordance with article 4, paragraph 2, subparagraph (b), submit the case to its competent authorities for the purpose of

prosecution, unless otherwise requested by the requesting Party for the purposes of preserving its legitimate jurisdiction.

10. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested Party, the requested Party shall, if its law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence which has been imposed under the law of the requesting Party, or the remainder thereof.

11. The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.

12. The Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements, whether ad hoc or general, on the transfer to their country of persons sentenced to imprisonment and other forms of deprivation of liberty for offences to which this article applies, in order that they may complete their sentences there.

Article 7

Mutual legal assistance

1. The Parties shall afford one another, pursuant to this article, the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to criminal offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

(a) Taking evidence or statements from persons;

(b) Effecting service of judicial documents;

(c) Executing searches and seizures;

(d) Examining objects and sites;

(e) Providing information and evidentiary items;

(f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including bank, financial, corporate or business records;

(g) Identifying or tracing proceeds, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes.

3. The Parties may afford one another any forms of mutual legal assistance allowed by the domestic law of the requested Party.

4. Upon request, the Parties shall facilitate or encourage, to the extent consistent with their domestic law and practice, the presence or availability of persons, including persons in custody, who consent to assist in investigations or participate in proceedings.

5. A Party shall not decline to render mutual legal assistance under this article on the ground of bank secrecy.

6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance in criminal matters.

7. Paragraphs 8 to 19 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If these Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the Parties agree to apply paragraphs 8 to 19 of this article in lieu thereof.

8. Parties shall designate an authority, or when necessary authorities, which shall have the responsibility and power to execute requests for mutual legal assistance or to transmit them to the competent authorities for execution. The authority or the authorities designated for this purpose shall be notified to the Secretary-General. Transmission of requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be effected between the authorities designated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that such requests and communications be addressed to it through the diplomatic channel and, in urgent circumstances, where the Parties agree, through channels of the International Criminal Police Organization, if possible.

9. Requests shall be made in writing in a language acceptable to the requested Party. The language or languages acceptable to each Party shall be notified to the Secretary-General. In urgent circumstances, and where agreed by the Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.

10. A request for mutual legal assistance shall contain:

(a) The identity of the authority making the request;

- (b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or proceeding to which the request relates, and the name and the functions of the authority conducting such investigation, prosecution or proceeding;
 - (c) A summary of the relevant facts, except in respect of requests for the purpose of service of judicial documents;
 - (d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure the requesting Party wishes to be followed;
 - (e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned;
 - (f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.
11. The requested Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.
12. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.
13. The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.
14. The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.
15. Mutual legal assistance may be refused:
- (a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;
 - (b) If the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, other public or other essential interests;
 - (c) If the authorities of the requested Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or proceedings under their own jurisdiction;
 - (d) If it would be contrary to the legal system of the requested Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.
16. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.

17. Mutual legal assistance may be postponed by the requested Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Party shall consult with the requesting Party to determine if the assistance can still be given subject to such terms and conditions as the requested Party deems necessary.

18. A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially informed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will.

19. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed by the Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

20. The Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to, or enhance the provisions of this article.

Article 8

Transfer of proceedings

The Parties shall give consideration to the possibility of transferring to one another proceedings for criminal prosecution of offences established in accordance with article 3, paragraph 1, in cases where such transfer is considered to be in the interests of a proper administration of justice.

Article 9

Other forms of co-operation and training

1. The Parties shall co-operate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, with a view to enhancing the effectiveness of law enforcement action suppress the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. They shall, in particular, on the basis of bilateral or multilateral agreements or arrangements:

(a) Establish and maintain channels of communication between their competent agencies an services to facilitate the secure and rapid exchange of information

746 GI/II-13

concerning all aspects of offences established in accordance with article 3, paragraph 1, including, if the Parties concerned deem it appropriate, links, with other criminal activities;

(b) Co-operate with one another in conducting enquiries, with respect to offences established in accordance with article 3, paragraph 1, having an international character, concerning:

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of being involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1;

(ii) The movement of proceeds or property derived from the commission of such offences;

(iii) The movement of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II of this Convention and instrumentalities used or intended for use in the commission of such offences;

(c) In appropriate cases and if not contrary to domestic law, establish joint teams, taking into account the need to protect the security of persons and of operations, to carry out the provisions of this paragraph. Officials of any Party taking part in such teams shall act as authorized by the appropriate authorities of the Party in whose territory the operation is to take place; in all such cases, the Parties involved shall ensure that the sovereignty of the Party on whose territory the operation is to take place is fully respected;

(d) Provide, when appropriate, necessary quantities of substances for analytical or investigative purposes;

(e) Facilitate effective co-ordination between their competent agencies and services and promote the exchange of personnel and other experts, including the posting of liaison officers.

2. Each Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement and other personnel, including customs, charged with the suppression of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. Such programmes shall deal, in particular, with the following:

(a) Methods used in the detection and suppression of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;

(b) Routes and techniques used by persons suspected of being involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, particularly in transit States, and appropriate counter-measures;

(c) Monitoring of the import and export of narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II;

(d) Detection and monitoring of the movement of proceeds and property derived from, and narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II, and instrumentalities used or intended for use in, the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;

(e) Methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property and instrumentalities;

(f) Collection of evidence;

(g) Control techniques in free trade zones and free ports;

(h) Modern law enforcement techniques.

3. The Parties shall assist one another to plan and implement research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 2 of this article and, to this end, shall also, when appropriate, use regional and international conferences and seminars to promote co-operation and stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of transit States.

Article 10

International co-operation and assistance for transit States

1. The Parties shall co-operate, directly or through competent international or regional organizations, to assist and support transit States and, in particular, developing countries in need of such assistance and support, to the extent possible, through programmes of technical co-operation on interdiction and other related activities.

2. The Parties may undertake, directly or through competent international or regional organizations, to provide financial assistance to such transit States for the purpose of augmenting and strengthening the infrastructure needed for effective control and prevention of illicit traffic.

3. The Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to this article and may take into consideration financial arrangements in this regard.

Article 11

Controlled delivery

1. If permitted by the basic principles of their respective domestic legal systems, the Parties shall take the necessary measures, within their possibilities, to allow for the appropriate use of controlled delivery at the international level, on the basis of agreements or arrangements mutually consented to, with a view to identifying persons involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, and to taking legal action against them.

2. Decisions to use controlled delivery shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the Parties concerned.

3. Illicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, with the consent of the Parties concerned, be intercepted and allowed to continue with the narcotic drugs or psychotropic substances intact or removed or replaced in whole or in part.

Article 12

Substances frequently used in the illicit Manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances

1. The Parties shall take the measures they deem appropriate to prevent diversion of substances in Table I and Table II used for the purpose of illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and shall co-operate with one another to this end.

2. If a Party or the Board has information which in its opinion may require the inclusion of a substance in Table I or Table II, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of that notification. The procedure described in paragraphs 2 to 7 of this article shall also apply when a Party or the Board has information justifying the deletion of a substance from Table I or Table II, or the transfer of a substance from one Table to the other.

3. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission, and, where notification is made by a Party, to the Board. The Parties shall communicate their comments concerning the notification to the Secretary-General, together with all supplementary information which may assist the Board in establishing an assessment and the Commission in reaching a decision.

4. If the Board, taking into account the extent, importance and diversity of the licit use of the substance, and the possibility and ease of using alternate substances both for licit purposes and for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, finds:

(a) That the substance is frequently used in the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance;

(b) That the volume and extent of the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance creates serious public health or social problems, so as to warrant international action, it shall communicate to the Commission an assessment of the substance, including the likely effect of adding the substance to either Table I or Table II on both licit use and illicit manufacture, together with recommendations of monitoring measures, if any, that would be appropriate in the light of its assessment.

5. The Commission, taking into account the comments submitted by the Parties and the comments and recommendations of the Board, whose assessment shall be

determinative as to scientific matters, and also taking into due consideration any other relevant factors, may decide by a two-thirds majority of its members to place a substance in Table I or Table II.

6. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention and to the Board. Such decision shall become fully effective with respect to each Party one hundred and eighty days after the date of such communication.

7. (a) The decisions of the Commission taken under this article shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within one hundred and eighty days after the date of notification of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary-General, together with all relevant information upon which the request for review is based.

(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and the relevant information to the Commission, to the Board and to all the Parties, inviting them to submit their comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for consideration.

(c) The Council may confirm or reverse the decision of the Commission. Notification of the Council's decision shall be transmitted to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, to the Commission and to the Board.

8. (a) Without prejudice to the generality of the provisions contained in paragraph 1 of this article and the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the Parties shall take the measures they deem appropriate to monitor the manufacture and distribution of substances in Table I and Table II which are carried out within their territory.

(b) To this end, the Parties may:

(i) Control all persons and enterprises engaged in the manufacture and distribution of such substances;

(ii) Control under license the establishment and premises in which such manufacture or distribution may take place;

(iii) Require that licensees obtain a permit for conducting the aforesaid operations;

(iv) Prevent the accumulation of such substances in the possession of manufacturers and distributors, in excess of the quantities required for the normal conduct of business and the prevailing market conditions.

9. Each Party shall, with respect to substances in Table I and Table II, take the following measures:

746 GI/11-14

(a) Establish and maintain a system to monitor international trade in substances in Table I and Table II in order to facilitate the identification of suspicious transactions. Such monitoring systems shall be applied in close co-operation with manufacturers, importers, exporters, wholesalers and retailers, who shall inform the competent authorities of suspicious orders and transactions.

(b) Provide for the seizure of any substance in Table I or Table II if there is sufficient evidence that it is for use in the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance.

(c) Notify, as soon as possible, the competent authorities and services of the Parties concerned if there is reason to believe that the import, export or transit of a substance in Table I or Table II is destined for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, including in particular information about the means of payment and any other essential elements which led to that belief.

(d) Require that imports and exports be properly labelled and documented. Commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other shipping documents shall include the names, as stated in Table I or Table II, of the substances being imported or exported, the quantity being imported or exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.

(e) Ensure that documents referred to in subparagraph (d) of this paragraph are maintained for a period of not less than two years and may be made available for inspection by the competent authorities.

10. (a) In addition to the provisions of paragraph 9, and upon request to the Secretary-General by the interested Party, each Party from whose territory a substance in Table I is to be exported shall ensure that, prior to such export, the following information is supplied by its competent authorities to the competent authorities of the importing country:

(i) Name and address of the exporter and importer and, when available, the consignee;

(ii) Name of the substance in Table I;

(iii) Quantity of the substance to be exported;

(iv) Expected point of entry and expected date of dispatch;

(v) Any other information which is mutually agreed upon by the Parties.

(b) A Party may adopt more strict or severe measures of control than those provided by this paragraph if, in its opinion, such measures are desirable or necessary.

11. Where a Party furnishes information to another Party in accordance with paragraph 9 and 10 of this article, the Party furnishing such information may require that the Party

receiving it keep confidential any trade, business, commercial or professional secret or trade process.

12. Each Party shall furnish annually to the Board, in the form and manner provided for by it and on forms made available by it, information on:

(a) The amounts seized of substances in Table I and Table II and, when known, their origin;

(b) Any substance not included in Table I or Table II which is identified as having been used in illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and which is deemed by the Part to be sufficiently significant to be brought to the attention of the Board;

(c) Methods of diversion and illicit manufacture.

13. The Board shall report annually to the Commission on the implementation of this article and the Commission shall periodically review the adequacy and propriety of Table I and Table II.

14. The provisions of this article shall not apply to pharmaceutical preparations, nor to other preparations containing substances in Table I or Table II that are compounded in such a way that such substances cannot be easily used or recovered by readily applicable means.

Article 13

Materials and equipment

The Parties shall take such measures as they deem appropriate to prevent trade in and the diversion of materials and equipment for illicit production or manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances and shall co-operate to this end.

Article 14

Measures to eradicate illicit cultivation of narcotic plants and to eliminate illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances

1. Any measures taken pursuant to this Convention by Parties shall not be less stringent than the provisions applicable to the eradication of illicit cultivation of plants containing narcotic and psychotropic substances and to the elimination of illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances under the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.

2. Each Party shall take appropriate measures to prevent illicit cultivation of and to eradicate plants containing narcotic or psychotropic substances, such as opium poppy, coca bush and cannabis plants, cultivated illicitly in its territory. The measures adopted shall respect fundamental human rights and shall take due account of traditional licit

uses, where there is historic evidence of such use, as well the protection of the environment.

3.-(a) The Parties may co-operate to increase the effectiveness of eradication efforts. Such co-operation may, inter alia, include support, when appropriate, for integrated rural development leading to economically viable alternatives to illicit cultivation.

Factors such as access to markets, the availability of resources and prevailing socio-economic conditions should be taken into account before such rural development programmes are implemented. The Parties may agree on any other appropriate measures of co-operation.

(b) The Parties shall also facilitate the exchange of scientific and technical information and the conduct of research concerning eradication.

(c) Whenever they have common frontiers, the Parties shall seek to co-operate in eradication programmes in their respective areas along those frontiers.

4. The Parties shall adopt appropriate measures aimed at eliminating or reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances, with a view to reducing human suffering and eliminating financial incentives for illicit traffic. These measures may be based, inter alia, on the recommendations of the United Nations, specialized agencies of the United Nations such as the World Health Organization, and other competent international organizations, and on the Comprehensive Multidisciplinary Outline adopted by the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, held in 1987, as it pertains to governmental and non-governmental agencies and private efforts in the fields of prevention, treatment and rehabilitation. The Parties may enter into bilateral or multilateral agreements or arrangements aimed at eliminating or reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances.

5. The Parties may also take necessary measures for early destruction or lawful disposal of the narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II which have been seized or confiscated and for the admissibility as evidence of duly certified necessary quantities of such substances.

Article 15

Commercial carriers

1. The Parties shall take appropriate measures to ensure that means of transport operated by commercial carriers are not used in the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1; such measures may include special arrangements with commercial carriers.

2. Each Party shall require commercial carriers to take reasonable precautions to prevent the use of their means of transport for the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. Such precautions may include:

(a) If the principal place of business of a commercial carrier is within the territory of the Party:

(i) Training of personnel to identify suspicious consignments or persons;

(ii) Promotion of integrity of personnel;

(b) If a commercial carrier is operating within the territory of the Party:

(i) Submission of cargo manifests in advance, whenever possible;

(ii) Use of tamper-resistant, individually verifiable seals on containers;

(iii) Reporting to the appropriate authorities at the earliest opportunity all suspicious circumstances that may be related to the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

3. Each Party shall seek to ensure that commercial carriers and the appropriate authorities at points of entry and exit and other customs control areas cooperate, with a view to preventing unauthorized access to means of transport and cargo and to implementing appropriate security measures.

Article 16

Commercial documents and labelling of exports

1. Each Party shall require that lawful exports of narcotic drugs and psychotropic substances be properly documented. In addition to the requirements for documentation under article 31 of the 1961 Convention, article 31 of the 1961 Convention as amended and article 12 of the 1971 Convention, commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other shipping documents shall include the names of the narcotic drugs and psychotropic substances being exported as set out in the respective Schedules of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the quantity being exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.

2. Each Party shall require that consignments of narcotic drugs and psychotropic substances being exported be not mislabelled.

Article 17

Illicit traffic by sea

1. The Parties shall co-operate to the fullest extent possible to suppress illicit traffic by sea, in conformity with the international law of the sea.

2. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel flying its flag or not displaying a flag or marks of registry is engaged in illicit traffic may request the

746 GI/11-15

assistance of other Parties in suppressing its use for that purpose. The Parties so requested shall render such assistance within the means available to them.

3. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law and flying the flag or displaying marks of registry of another Party is engaged in illicit traffic may so notify the flag State, request confirmation of registry and, if confirmed, request authorization from the flag State to take appropriate measures in regard to that vessel.

4. In accordance with paragraph 3 or in accordance with treaties in force between them or in accordance with any agreement or arrangement otherwise reached between those Parties, the flag State may authorize the requesting State to, *inter alia*:

a) Board the vessel;

b) Search the vessel;

c) If evidence of involvement in illicit traffic is found, take appropriate action with respect to the vessel, persons and cargo on board.

5. Where action is taken pursuant to this article, the Parties concerned shall take due account of the need not to endanger the safety of life at sea, the security of the vessel and the cargo or to prejudice the commercial and legal interests of the flag State or any other interested State.

6. The flag State may, consistent with its obligations in paragraph 1 of this article, subject its authorization to conditions to be mutually agreed between it and the requesting Party, including conditions relating to responsibility.

7. For the purposes of paragraphs 3 and 4 of this article, a Party shall respond expeditiously to a request from another Party to determine whether a vessel that is flying its flag is entitled to do so, and to requests for authorization made pursuant to paragraph

3. At the time of becoming a Party to this Convention, each Party shall designate an authority or, when necessary, authorities to receive and respond to such requests. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other Parties within one month of the designation.

8. A Party which has taken any action in accordance with this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that action.

9. The Parties shall consider entering into bilateral or regional agreements or arrangements to carry out, or to enhance the effectiveness of, the provisions of this article.

10. Action pursuant to paragraph 4 of this article shall be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.

11. Any action taken in accordance with this article shall take due account of the need not to interfere with or affect the rights and obligations and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of the sea.

Article 18

Free trade zones and free ports

1. The Parties shall apply measures to suppress illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II in free trade zones and in free ports that are not less stringent than those applied in other parts of their territories.

2. The Parties shall endeavour:

(a) To monitor the movement of goods and persons in free trade zones and free ports, and, to that end, shall empower the competent authorities to search cargoes and incoming and outgoing vessels, including pleasure craft and fishing vessels, as well as aircraft and vehicles and, when appropriate, to search crew members, passengers and their baggage;

(b) To establish and maintain a system to detect consignments suspected of containing narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II passing into or out of free trade zones and free ports;

(c) To establish and maintain surveillance systems in harbour and dock areas and at airports and border control points in free trade zones and free ports.

Article 19

The use of the mails

1. In conformity with their obligations under the Conventions of the Universal Postal Union, and in accordance with the basic principles of their domestic legal systems, the Parties shall adopt measures to suppress the use of the mails for illicit traffic and shall co-operate with one another to that end.

2. The measures referred to in paragraph 1 of this article shall include, in particular:

(a) Co-ordinated action for the prevention and repression of the use of the mails for illicit traffic;

(b) Introduction and maintenance by authorized law enforcement personnel of investigative and control techniques designed to detect illicit consignments of narcotic drugs, psychotropic substances in Table I and Table II in the mails;

c) Legislative measures to enable the use of appropriate means to secure evidence required for judicial proceedings.

Article 20

Information to be furnished by the Parties

1. The Parties shall furnish, through the Secretary-General, information to the Commission on the working of this Convention in their territories and, in particular:

(a) The text of laws and regulations promulgated in order to give effect to the Convention;

(b) Particulars of cases of illicit traffic within their jurisdiction which they consider important because of new trends disclosed, the quantities involved, the sources from which the substances are obtained, or the methods employed by persons so engaged.

2. The Parties shall furnish such information in such a manner and by such dates as the Commission may request.

Article 21

Functions of the Commission

The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims of this Convention and, in particular:

(a) The Commission shall, on the basis of the information submitted by the Parties in accordance with article 20, review the operation of this Convention;

(b) The Commission may make suggestions and general recommendations based on the examination of the information received from the Parties;

(c) The Commission may call the attention of the Board to any matters which may be relevant to the functions of the Board;

(d) The Commission shall, on any matter referred to it by the Board under article 22, paragraph 1 (b), take such action as it deems appropriate;

(e) The Commission may, in conformity with the procedures laid down in article 12, amend Table I and Table II;

(f) The Commission may draw the attention of non-Parties to decisions and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their considering taking action in accordance therewith.

Article 22

Functions of the Board

1. Without prejudice to the functions of the Commission under article 21, and without prejudice to the functions of the Board and the Commission under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention:

(a) If, on the basis of its examination of information available to it, to the Secretary-General or to the Commission, or of information communicated by United Nations organs, the Board has reason to believe that the aims of this Convention in matters related to its competence are not being met, the Board may invite a Party or Parties to furnish any relevant information;

(b) With respect to articles 12, 13 and 16:

(i) After taking action under subparagraph (a) of this article, the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Party concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of articles 12, 13 and 16;

(ii) Prior to taking action under (iii) below, the Board shall treat as confidential its communications with the Party concerned under the preceding subparagraphs;

(iii) If the Board finds that the Party concerned has not taken remedial measures which it has been called upon to take under this subparagraph, it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter. Any report published by the Board under this subparagraph shall also contain the views of the Party concerned if the latter so requests.

2. Any Party shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question of direct interest to it is to be considered under this article.

3. If in any case a decision of the Board which is adopted under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.

4. Decisions of the board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board.

5. In carrying out its functions pursuant to subparagraph 1 (a) of this article, the Board shall ensure the confidentiality of all information which may come into its possession.

746 GI/II-16

6. the Board's responsibility under this article shall not apply to the implementation of treaties or agreements entered into between Parties in accordance with the provisions of this Convention.

7. The provisions of this article shall not be applicable to disputes between Parties falling under the provisions of article 32.

Article 23

Reports of the Board

1. The Board shall prepare an annual report on its work containing an analysis of the information at its disposal and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Parties, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. The Board may make such additional reports as it considers necessary. The reports shall be submitted to the Council through the Commission which may make such comments as it sees fit.

2. The reports of the Board shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unrestricted distribution.

Article 24

Application of stricter measures than those required by this Convention

A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic.

Article 25

Non-derogation from earlier treaty rights and obligations

The provisions of this Convention shall not derogate from any rights enjoyed or obligations undertaken by Parties to this Convention under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.

Article 26

Signature

This Convention shall be open for signature at the United Nations Office at Vienna, from 20 December 1988 to 28 February 1989, and thereafter at the Headquarters of the United Nations at New York, until 20 December 1989, by:

(a) All States;

(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia;

(c) Regional economic integration organizations which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Convention, references under the Convention to Parties, States or national services being applicable to these organizations within the limits of their competence.

Article 27

Ratification, acceptance, approval or act of formal confirmation

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States and by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and to acts of formal confirmation by regional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph (c). The instruments of ratification, acceptance or approval and those relating to acts of formal confirmation shall be deposited with the Secretary-General.

2. In their instruments of formal confirmation, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention. These organizations shall also inform the Secretary-General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention.

Article 28

Accession

1. This Convention shall remain open for accession by any State, by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and by regional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph (c). Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.

2. In their instruments of accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention. These organizations shall also inform the Secretary-General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention.

Article 29

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or by Namibia, represented by the Council for Namibia.

746 GI/11-17

2. For each State or for Namibia, represented by the Council for Namibia, ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. for each regional economic integration organization referred to in article 26, subparagraph (c) depositing an instrument relating to an act of formal confirmation or an instrument of accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after such deposit, or at the date the Convention enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is later.

Article 30

Denunciation

1. A Party may denounce this Convention at any time by a written notification addressed to the Secretary-General.
2. Such denunciation shall take effect for the Party concerned one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article 31

Amendments

1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated by that Party to the Secretary-General, who shall communicate it to the other Parties and shall ask them whether they accept the proposed amendment. If a proposed amendment so circulated has not been rejected by any Party within twenty-four months after it has been circulated, it shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in respect of a Party ninety days after that Party has deposited with the Secretary-General an instrument expressing its consent to be bound by that amendment.
2. If a proposed amendment has been rejected by any Party, the Secretary-General shall consult with the Parties and, if a majority so requests, he shall bring the matter, together with any comments made by the Parties, before the Council which may decide to call a conference in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations. Any amendment resulting from such a Conference shall be embodied in a Protocol of Amendment. Consent to be bound by such a Protocol shall be required to be expressed specifically to the Secretary-General.

Article 32**Settlement of disputes**

1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.
2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article shall be referred, at the request of any one of the States Parties to the dispute, to the International Court of Justice for decision.
3. If a regional economic integration organization referred to in article 26, subparagraph (c) is a Party to a dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article, it may, through a State Member of the United Nations, request the Council to request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with Article 65 of the Statute of the Court, which opinion shall be regarded as decisive.
4. Each State, at the time of signature or ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, or each regional economic integration organization, at the time of signature or deposit of an act of formal confirmation or accession, may declare that it does not consider itself bound by paragraphs 2 and 3 of this article. The other Parties shall not be bound by paragraphs 2 and 3 with respect to any Party having made such a declaration.
5. Any Party having made a declaration in accordance with paragraph 4 of this article may at any time withdraw the declaration by notification to the Secretary-General.

Article 33**Authentic texts**

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention are equally authentic.

Article 34

The Secretary General shall be the depositary of this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE AT VIENNA, in one original, this twentieth day of December one thousand nine hundred and eighty-eight.

Now therefore, in the exercise of the powers conferred by sub-section of 4 of Section 3 of the Indian Extradition Act 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provision of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Republic of Croatia with effect from the date of publication of this notification, in respect of the offences specified in the above Convention.

[F. No. T-413/84/2010]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)